

मुकदमों का विवरण

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी

वी.

हीराल सोमाभाई ठेकेदार (निर्णयित) प्रतिनिधि। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा

(सिविल अपील सं. 2022 की 4955) सितंबर 06, 2023

[जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्दे: क्या अपने मुवक्किल की ओर से एक वकील/अधिवक्ता द्वारा अदालत को दिए गए वचन के रूप में किसी आश्वासन का जानबूझकर उल्लंघन "दीवानी अवमानना" के रूप में माना जाएगा। 2(ख) न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 का; क्या यह कहा जा सकता है कि उक्त वचन न्यायालय को दिया गया था; क्या अवमानना न्यायालय को किसी भी अवमाननापूर्ण लेनदेन को अवैध या शून्य घोषित करने की शक्ति है; क्या अवमानना लेनदेन के लाभार्थी को इस आधार पर अवमानना कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है कि वे आवश्यक या उचित पक्ष हैं क्योंकि वे बिना किसी सूचना के मूल्य के लिए वाद संपत्ति के वास्तविक खरीदार हैं; और क्या अवमानकर्ताओं द्वारा दी गई माफी स्वीकार करने योग्य है।

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 - धारा 19 के तहत सांविधिक अपील-उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानकों की ओर से पेश वकील द्वारा मुवक्किलों के निर्देशों पर एक वचन के रूप में दिया गया बयान कि संपत्ति को मुख्य याचिका के निपटारे तक नहीं बेचा जाएगा-हालांकि, वचन के बावजूद, अपीलकर्ता विभिन्न पक्षकारों के पक्ष में बिक्री विलेखों को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़े और इस तरह, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की-उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए और बिक्री लेनदेन को शून्य माना गया-शुद्धता:

आयोजित किया गया: उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की-उच्च न्यायालय को वचन दिया गया था और उल्लंघन या अवज्ञा 1971 के अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करेगी। [पारस 116 और 117]

1064 1065

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 - धारा 2 (बी)-अभिव्यक्ति 'जानबूझकर अवज्ञा'-जिसका अर्थ है-अपने मुवक्किल की ओर से अदालत में एक वकील/अधिवक्ता द्वारा दिए गए वचन के रूप में आश्वासन का जानबूझकर उल्लंघन, यदि यह 'नागरिक अवमानना' के रूप में मान लिया जाता है। 2(ख):

आयोजित किया गया: "जानबूझकर" अभिव्यक्ति का अर्थ है ऐसा कार्य या चूक जो स्वेच्छा से या जानबूझकर किया जाता है और कुछ ऐसा करने के इरादे से किया जाता है जिसे कानून मना करता है या विशेष इरादे से कुछ ऐसा करने में विफल रहने के इरादे से जो कानून को करने की आवश्यकता है, या तो कानून की अवज्ञा करने के लिए या कानून की अवहेलना करने के लिए-यह बुरी मंशा से या बुरे इरादे या उद्देश्य से की गई जानबूझकर कार्यवाई को दर्शाता है-अदालत में अपने मुवक्किल की ओर से एक वकील/अधिवक्ता द्वारा दिए गए वचन के रूप में आश्वासन, उसी का जानबूझकर उल्लंघन या अवज्ञा करना 'नागरिक अवमानना' के रूप में माना जाएगा। 2((ख) 1971 अधिनियम। [पैरा 56 और 116 (i)]

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 - धारा 2 (बी)-कार्यकाल उपक्रम-जिसका अर्थ है-अधिवक्ता द्वारा उपक्रम, यदि न्यायालय को वचन दिया गया है:

आयोजित किया गया: मुकदमे में किसी पक्ष द्वारा दिया गया प्रत्येक वचन न्यायालय के लिए एक वचन नहीं हो सकता है-किसी पक्ष को दिए गए वचन और अदालत को दिए गए वचन के बीच एक अंतर मौजूद है-अदालत को दिया गया वचन 1971 के अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करता है, जबकि समझौते के समझौते के माध्यम से किसी पक्ष को दिया गया वचन या

अन्यथा 1971 के अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है-दूसरे पक्ष को दिए गए वचन का उल्लंघन अदालत की अवमानना का गठन नहीं कर सकता है-हालाँकि, क्या कोई विशेष वचन अदालत या विपरीत पक्ष के लिए एक वचन है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और उपयोग की गई भाषा पर निर्भर करता है-तथ्यों पर, वचन को अदालत को दिया गया कहा जा सकता है-जानबूझकर आश्वासन का उल्लंघन।2(बी)।[पैरा 72,73,76-77 और 116 (ii)]

अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971-अदालत की अवमानना-अवमानना की कार्यवाही में मुकदमे की संपत्ति का हस्तांतरण-किसी भी अवमाननापूर्ण लेनदेन को अवैध या शून्य घोषित करने की अवमानना अदालत की शक्ति:

1066

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

आयोजित किया गया:यद्यपि मुकदमे की संपत्ति के हस्तांतरण को शुरू से ही अमान्य नहीं कहा जा सकता है, फिर भी जब अदालत अवमानना की कार्यवाही में ऐसे हस्तांतरणों पर विचार कर रही है तो अदालत कानून की महिमा बनाए रखने के लिए ऐसे लेनदेन को अमान्य घोषित कर सकती है-अवमानना करने वाले को दंडित करने के अलावा, कानून की महिमा मांग कर सकती है कि अदालत द्वारा या तो उक्त लेनदेन को अमान्य घोषित करके लेनदेन को उलटने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं या संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देने के लिए आगे बढ़े ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवमानना करने वाले की ओर से आपत्तिजनक आचरण अवमानना करने वाले या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए जारी न रहे-तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने सभी बिक्री विलेखों को निष्पादित घोषित करने में न्यायसंगत आदेश दिया।एस. 52.[पैरा 88,89 और 116 (iii)]

अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971-अदालत की अवमानना-अवमानना कार्यवाही-किसी भी आपत्तिजनक लेनदेन के लाभार्थियों को आवश्यक पक्षों के रूप में लागू करना:

आयोजित किया गया:किसी भी आपत्तिजनक लेन-देन के लाभार्थी सचिवों को अवमानना की कार्यवाही में इस आधार पर सुनवाई करने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं है कि वे बिना किसी सूचना के संपत्ति के वास्तविक खरीदार हैं और इस प्रकार, आवश्यक पक्ष हैं-अवमानना अदालत और अवमाननाकर्ता के बीच है और कोई तीसरा पक्ष इसमें खुद को शामिल नहीं कर सकता है-उच्च न्यायालय के लिए अवमानना की कार्यवाही में खरीदारों को शामिल करना आवश्यक नहीं था-खरीदार चुपचाप कार्यवाही देख रहे थे-ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन जब चीजें गलत हो गईं, तो वे अब पक्षकारों के रूप में शामिल नहीं किए जाने और उच्च न्यायालय द्वारा सुने जाने पर बुरा बोलते हैं-आवश्यक पक्षकार।[पैरा 97 और 116 (iv)]

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 -धारा 12-न्यायालय की अवमानना के लिए दंड-अवमानकर्ताओं द्वारा दी गई माफी-निम्नलिखित की स्वीकृति:

आयोजित किया गया:क्षमा याचना को निश्चित रूप से एक मामले के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और अदालत इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है-माफी बिना शर्त, अयोग्य और प्रामाणिक हो सकती है, फिर भी यदि आचरण गंभीर है, जिसने संस्था की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है, तो भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए-अदालतों द्वारा करुणा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, जब किसी वचन या आदेश की अवज्ञा दंड से मुक्त और पूरी चेतना के साथ हो-सभी उच्च 1067 के समक्ष कार्यवाही के दौरान।

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा

अदालत में, अपीलकर्ताओं का रुख यह था कि उन्होंने अदालत को एक स्पष्ट वचन देने के बावजूद बिक्री विलेखों को निष्पादित करके एक बड़ी गलती की कि वे ऐसा नहीं करेंगे-ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अनुरोध किया कि उनकी माफी स्वीकार की जा सकती है और उन्हें कार्यवाही से मुक्त किया जा सकता है-हालाँकि माफी उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार में दी गई थी, फिर भी ऐसी माफी स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं की गई थी।[पारस 100,113 और 116 (v)]

न्यायिक नोटिस-न्यायालय की अवमानना से संबंधित मामले:

आयोजित किया गया: यह देखा गया है कि अदालतों ने अवमानकों के प्रति अनुचित नरमी और उदारता दिखाई है-अदालतों द्वारा दिखाया गया उदार रवैया वास्तव में बेईमान वादियों को किसी भी अदालत द्वारा पारित आदेश या अदालत को दिए गए किसी भी वचन का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित करता है-अदालत की अवमानना के लिए आगे बढ़े वादियों ने महसूस किया है कि उनके हाथों में माफी के रूप में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है-अदालतों द्वारा करुणा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए जब किसी वचन या आदेश की अवज्ञा दंड से मुक्त और पूरी चेतना के साथ हो।[पारस 101 और 102]

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 -धारा 12-न्यायालय की अवमानना के लिए दंड-यू/एस से माफी।12 - की अवधारणा-समझाया गया।[अनुच्छेद 99,111,112] न्यायालय की अवमानना-अवमानना क्षेत्राधिकार-शासी सिद्धांतों का प्रयोग-उल्लिखित।[पारस 40-45]

न्यायालय की अवमानना-दीवानी अवमानना-संतुष्ट करने के लिए शर्तों का आयोग-कहा गया।[पैरा 43]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

मोहम्मद.असलम बनाम भारत संघ (1994) 6 एस. सी. सी. 442:[1994] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 104; राम नारंग बनाम रमेश नारंग और एक अन्य (2006) 11 एस. सी. सी. 114:[2006] 3 एससीआर 1068; अनिल के. सुराना और एक अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (2007) 10 एससीसी 257; बी हरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड बनाम आईएफसीआई लिमिटेड (2010) 14

एससीसी 77:[2010] 15 एस. सी. आर. 993; अभिषेक कुमार सिंह बनाम जी. पटनायक और

अन्य (2021) 7 एस. सी. सी. 613; मर्रे एंड कंपनी बनाम अशोक के. नेवटिया और एक और,

(2000) 2 एससीसी 367:[2000] 1 एस. सी. आर. 367; टी. रवि और एक अन्य बनाम बी. चिन्ना

1068

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

नरसिम्हा और अन्य (2017) 7 एस. सी. सी. 342:[2017] 3 एस. सी. आर. 1; सेवक्रम

प्रभुदास बनाम एच. एस. पटेल और अन्य, 2000 (1) खंड। 41 जीएलआर 715; मृत्युंजय दास और एक अन्य बनाम सैयद हसीबुर रहमान और अन्य, (2001) 3 एससीसी 739:[2001] 2 एस. सी. आर. 471; सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और

दूसरा, (1998) 4 एस. सी. सी. 409:[1998] 2 एससीआर 795; रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स

लिमिटेड वी.इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और

अन्य, (1988) 4 एससीसी 592:[1988] 3 पूरक।एससीआर 212; पटेल रजनीकांत

धुलाभाई और एक अन्य बनाम पटेल चंद्रकांत धुलाभाई और अन्य, (2008) 14 एससीसी 561:[2008] 10 एस. सी. आर. 1169; कंवर सिंह सैनी बनाम उच्च न्यायालय

दिल्ली (2012) 4 एस. सी. सी. 307:[2011] 15 एस. सी. आर. 972; नियाज मोहम्मद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (1994) 6 एस. सी. सी. 332:[1994] 3 पूरक।एससीआर

720; अशोक पेपर कामगार यूनियन बनाम धरण गोधा और अन्य, (2003) 11 एस. सी. सी. 1; राम किशन बनाम तरुण बजाज और अन्य, (2014) 16 एस. सी. सी. 204:[2014] 1 एस. सी. आर. 538; बजरंगलाल गंगाधर खेमका और एक अन्य बनाम कपूरचंद लिमिटेड. ए. आई. आर. 1950 बम 336; निशा कांतो रॉय चौधरी बनाम श्रीमती। सरोज बशीनी गोहो ए. आई. आर. 1948 कैल. 295; छाया देवी बनाम लाहोरीराम पराशर, (1962-63) 67 सी. डब्ल्यू. एन. 819; सुमन चड्ढा

और एक अन्य बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 11536; रीता मार्कडेय बनाम सुरजीत सिंह अरोड़ा, (1996) 6 एस. सी. सी.

14 :[1996] 7 पूरक।एससीआर 56; गोविंद कौर बनाम हरदेव 1982 (1) आरसीआर 323

(13); भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम डॉ. विजय माल्या, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 826; सत्यव्रत विश्वास और अन्य बनाम कल्याण कुमार किस्कु और अन्य

(1994) 2 एससीसी 266:[1994] 1 एस. सी. आर. 413; थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड बनाम

नानक बिल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (2013) 5 एस. सी. सी. 397:[2013] 2 एस. सी. आर. 74; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी।

(पी) लिमिटेड और अन्य, (1996) 4 एस. सी. सी. 622:[1996] 2 पूरक।एस. सी. आर. 295; विदुर

इम्पेक्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम तोश अपार्टमेंट प्राइवेट

लिमिटेड और अन्य, (2012) 8 एस. सी. सी. 384:[2012] 10 एस. सी. आर. 307; जहाँल तांती

और अन्य बनाम नागेश्वर सिंह (मृत) टीएचआर। एल. आर. एस., ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2235;

इन रे:मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1994 की ओ. जे. अपील सं. 16 ने 1994 की कंपनी याचिका सं. 22 में 12.07.1996 पर निर्णय लिया; सुरजीत सिंह और अन्य आदि।बनाम हरबंस सिंह और अन्य, ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 135:[1995] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 354; सरविंदर सिंह बनाम दलीप सिंह और अन्य, (1996) 5 एस. सी. सी. 539:[1996] 4 पूरक।एस. सी. आर. 271; बीबी जुबैदा खातून बनाम नबी हसन साहब और

दूसरा, (2004) 1 एस. सी. सी. 191:[2003] 5 पूरक।एस. सी. आर. 290; धुरंधर प्रसाद

सिंह बनाम जय प्रकाश विश्वविद्यालय और अन्य (2001) 6 एस. सी. सी. 534:[2001] 3 1069

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा

एससीआर 1129; डी. एन. तनेजा बनाम भजन लाल, (1988) 3 एससीसी 26:[1988] 3 एससीआर

888; तपन कुमार मुखर्जी बनाम हीरोमोनी मंडल और अन्य, (1991) 1 एस. सी. सी. 397:[1990] 3 पूरक।एस. सी. आर. 55; उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, होशंगाबाद बनाम जवाहर लाल रामचंद परवर ए. आई. आर. 1940 नागपुर 407; प्रिया गुप्ता और एक अन्य बनाम अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और

अन्य, (2013) 11 एससीसी 404:[2012] 12 एससीआर 818; एम. वाई. शरीफ और एक अन्य

नागपुर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश और अन्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 19

: [1955] एस. सी. आर. 757-संदर्भित।एम. वी.होम ऑफिसी सीई एंड अदर (1992) क्यू. बी. 270:(1992) 2 डब्ल्यूएलआर 73

: (1992) 4 सभी ईआर 97; क्लार्क और अन्य बनाम चैडबर्न और अन्य (1985) 1

सभी ई. आर. 211-संदर्भित।ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठा संस्करण, पृष्ठ 1599; ब्लैक लॉ डिक्शनरी, पांचवां संस्करण-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 4955।विविध क्षेत्रों में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 13.07.2022 के निर्णय और आदेश से।2013 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 16266 में 2018 का सिविल आवेदन No.121।

सह

सिविल अपील संख्या 2022 की 5041 और 2023 की 4869।

रूप:

श्याम दीवान, कपिल सिब्बल, मिहिर जोशी, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, गौरव सिंह, सौमिक घोषाल, शमिक शिरीषभाई संजनवाला, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, वंशदीप डालमिया, सुश्री देवांशी सिंह, शिवम पुंथीर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, नचिकेत ए. डेव, प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित, अलापति साहित्य कृष्ण, सुश्री निधि मित्तल, ऋषभ एन. कपाडिया, विजयानंद त्रिपाठी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

1070 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय
का निर्णय/आदेश

न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला, जे.:

“जब हम अपने देश की विशेषता के रूप में 'कानून के शासन' की बात करते हैं, (हमारा मतलब है) तो न केवल यह कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, बल्कि (एक अलग बात क्या है) कि यहां प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद या स्थिति कुछ भी हो, क्षेत्र के सामान्य कानून के अधीन है और सामान्य न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है।कानून और उसकी संस्थाओं के प्रति सम्मान ही एकमात्र आश्वासन है जो एक बहुलवादी राष्ट्र को एकजुट रख सकता है।हालाँकि, वैचारिक और भावनात्मक रूप से अधिभारित विवादों का समाधान करने का कोई भी प्रयास, कानून और न्यायिक संस्थानों के आधार पर नहीं, बल्कि संख्या के बल पर, हमारे चुने हुए राजनीतिक संगठन के मौलिक मूल्यों को नष्ट कर देगा।यह स्वीकृत संवैधानिक संस्थानों में जनता के विश्वास को ध्वस्त कर देगा और शांतिपूर्ण तरीकों से मुद्दों को हल करने के लोगों के संकल्प को कमजोर कर देगा।यह कानून के शासन और अदालतों के अधिकार के प्रति सम्मान को नष्ट कर देगा और व्यक्तिगत अधिकार और संख्या की ताकत को कानून के विवेक से ऊपर रखने की कोशिश करेगा।”

मोहम्मद.असलम बनाम भारत संघ, (1994) 6 एस. सी. सी. 442।

1. चूंकि सभी शीर्षक वाली अपीलों में उठाए गए मुद्दे समान हैं; पक्ष भी समान हैं और चुनौती गुजरात के उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्वयं के फैसले के लिए भी है, जिन्हें समान रूप से सुनवाई के लिए लिया गया था और इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।2. हमारे सामने तीनों अपीलें हैं।

3. 2022 की सिविल अपील संख्या 4955 और 2022 की सिविल अपील संख्या 5041 अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 (संक्षेप में, 'अधिनियम 1971') की धारा 19 (1) के तहत वैधानिक अपीलें हैं, जिनके नेतृत्व में अवमानकर्ताओं को उच्च न्यायालय द्वारा दंडित किया गया था, जबकि 2023 की सिविल अपील संख्या 4869 एक अपील है जो इस न्यायालय की अनुमति से अवमानना लेनदेन के लाभार्थियों के कहने पर की गई है।दूसरे शब्दों में, 2023 की सिविल अपील संख्या 4869 के अपीलार्थी अवमानकर्ताओं से वाद संपत्तियों के खरीदार हैं।अवमानना लेनदेन के लाभार्थी भी 1071 हैं।

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1072 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

उच्च न्यायालय के रूप में इस न्यायालय के समक्ष ऊपर निर्दिष्ट दो वैधानिक अपीलों के अपीलार्थियों को अदालत को दिए गए वचन की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराते हुए बिक्री लेनदेन को भी अमान्य घोषित कर दिया।

न्यायालय अधिनियम, **1971** की धारा **19** के तहत सांविधिक आवेदन

4. दो सांविधिक अपीलों के अपीलार्थियों को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित न्यायालय को दिए गए वचन की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया गया है, जिसे 2013 के विशेष नागरिक आवेदन संख्या 16266 में पारित 14.10.2015 के आदेश के माध्यम से दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को दिनांक 13.07.2022 की अवमानना का दोषी ठहराते हुए पारित किया गया विवादित आदेश विविध मामलों में पारित किया गया। 2013 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 16266 में उत्तरदाताओं के नेतृत्व में 2018 के सिविल आवेदन No.121। 5. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश का कार्यात्मक भाग इस प्रकार है:

“आदेश

(i) हम मानते हैं कि अभियुक्त संख्या 3.1 से 3.4 और अभियुक्त संख्या 4 इस न्यायालय को दिए गए वचन की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना का दोषी है जो 2013 के विशेष नागरिक आवेदन संख्या 16266 में पारित आदेश द्वारा दर्ज किया गया था।

((ii) हम रुपये की लागत लगाते हैं। 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) अभियुक्तों को कारावास की सजा सुनाने के बदले में 3 और 3 पर और इसके अलावा उन्हें 5 लाख रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दें। 2, 000/- (केवल दो हजार रुपये) और शुल्क की राशि का भुगतान आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा और इसकी चूक में उन्हें दो (2) महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा।

((ग) हम अभियुक्त सं. 3.3, 3 और अभियुक्त सं. 4 को दो महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाते हैं और एक लाख रुपये का जुर्माना देते हैं। 2, 000/- (केवल दो हजार रुपये) और चूक में दो (2) महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा।

((iv) यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित बिक्री विलेख अभियुक्त सं. 3.1 से 3.3 तक अभियुक्त सं. 4 खरीदार के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में और इसे रद्द करने, रद्द करने और अलग करने का आदेश दिया जाता है और उत्तरदाताओं को उस स्थिति को बहाल करने का निर्देश दिया जाता है जो उपरोक्त बिक्री विलेखों के निष्पादन से पहले प्रचलित थी जो 2013 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 16266 में पारित आदेश के समय प्रचलित थी।

उक्त बिक्री विलेख इस प्रकार हैं:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

बिक्री विलेख **1073** की सूची

श्री. नहीं।	बिक्री विलेख तिथि	प्लॉट क्षेत्र	प्लॉट नं.	विचार का नाम	खरीदार
1	9-11-15	118.48	79	103115/-	जगदीश चुग
2	9-11-15	118.48	80	103115/-	रमा रानी
3	19-2-16	118.48	119 ए.	8500/-	प्रकाश कुंडू
4	19-2-16	118.48	199 बी.	8500/-	प्रकाश कुंडू
5	19-2-16	118.48	200	8500/-	प्रकाश कुंडू
6	15-3-16	118.48	122 बी (56)	8500/-	मफतलाल कालिदास

					एचयूएफ
7	15-3-16	118.48	122 सी (55)	8500/-	मफतलाल कालिदास एचयूएफ
8	17-5-17	152	27	8500/-	सुदेश डिंगरा
9	17-5-17	152	27 ए.	8500/-	शिल्पी रवि
10	17-5-17	152	28	8500/-	रोशन लाल
11	25-7-17	118.48	176	8500/-	सामी कुमार
				2,82,730/-	
3 बिक्री विलेख बाद में किए गए/जोड़े गए					
12	30-10-18	19.26	दुकान संख्या 7	49000/-	त्रिलोकराम माली
13	25-7-17	118.48	175	8500/-	योगेश कुमार पटेल
कुल			3,40,230/-		

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1074

क्षेत्राधिकार उप-पंजीयक को तदनुसार अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के लिए सूचित किया जाए।

(v) यह खरीदारों के लिए खुला होगा कि वे अभियुक्त सं. 3.1 से 3.4 और अभियुक्त सं. 3 से बिक्री प्रतिफल की राशि की वसूली कर सकें। 4.

(vi) वर्तमान विविध।सिविल आवेदन की अनुमति है जिसकी लागत रु। 1,00,000-अभियुक्त एन. ओ. एस. द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से देय। 3. 1 से 3.4 तक और अभियुक्त नं। 4 वर्तमान कार्यवाहियों की लागत के लिए आवेदकों को।

64. उपरोक्त आदेश की घोषणा के बाद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिहिर जोशी ने चार सप्ताह की अवधि के लिए इस फैसले के संचालन पर रोक लगाने की मांग की है।उपरोक्त मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि आज से चार सप्ताह की अवधि के लिए इस आदेश पर रोक लगाना उचित और आवश्यक होगा।तदनुसार, हम आज से चार सप्ताह की अवधि के लिए इस निर्णय पर रोक लगाते हैं, बशर्ते कि अभियुक्त संख्या 3.1 से 3.4 और अभियुक्त संख्या 4 ने आज से दो सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आदेश के अनुसार राशि और लागत जमा की हो।"

6.....यह सब उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2015 की सिविल अपील संख्या 11412 में 2013 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 16266 में पारित एक आदेश के साथ शुरू हुआ।ऊपर निर्दिष्ट 14.10.2015 दिनांकित आदेश इस प्रकार है:

"श्री संजनवाला द्वारा बार में अपने मुवक्किलों के निर्देश पर कहा गया है कि इस प्रविष्टि और याचिका की विषय वस्तु वाली संपत्ति को तब तक नहीं बेचा जाएगा जब तक कि मुख्य याचिका की सुनवाई और निर्णय नहीं हो जाता है, जो श्री मिहिर ठाकुर के श्री प्रभाव मेहता के साथ उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की चेतना को संतुष्ट करता है और वह कहता है कि वह निर्देशों पर लेटर्स पेटेंट अपील को दबा नहीं सकता है।इसलिए, इस सिविल आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है।यह बिना कहे चला जाता है कि आदेश विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से पारित किया गया था।"

(बल दिया गया)

[2023] 11 एस सी आर।

7. इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा एक वचन पत्र के रूप में एक बयान दिया गया था और वह भी मुवक्किलों के निर्देशों पर कि विषय वस्तु यानी संपत्ति को तब तक नहीं बेचा जाएगा जब तक कि मुख्य याचिका यानी 2013 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 16266 का निपटान नहीं किया जाता है।

8. उपरोक्त आदेश के बल पर एक अंतरिम आदेश के खिलाफ उत्तरदाताओं के नेतृत्व में एक लेटर्स पेटेंट अपील (एल. पी. ए.) का भी निपटान दिनांक 21.10.2015 के आदेश के माध्यम से किया गया, जो इस प्रकार है:

“श्री प्रभाव मेहता ने आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि 2013 के एस. सी. ए. संख्या 16266 में 2015 के सिविल आवेदन संख्या 11412 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 14 अक्टूबर, 2015 के आदेश को देखते हुए, जिसमें बयान दर्ज किया गया है कि इस प्रविष्टि की विषय वस्तु को तब तक नहीं बेचा जाएगा जब तक कि मुख्य याचिका की सुनवाई और निर्णय नहीं हो जाता है, वह कार्यवाही को वापस लेने की अनुमति मांगता है। अनुमति दी जाती है। तदनुसार, 2015 की सिविल आवेदन संख्या 10627 और 2013 की एस. सी. ए. संख्या 16266 में 2015 की एल. पी. ए. (स्टाम्प) संख्या 1195 का निपटान 2015 की सिविल आवेदन (स्टाम्प) संख्या 10539 के साथ वापस लिए जाने के रूप में किया जाएगा।”

(जोर दिया गया) 9. ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वीकार करने के बावजूद कि विवादित प्रविष्टि की विषय वस्तु का निपटारा मुख्य मामले के अंतिम निपटारे तक नहीं किया जाएगा; इसमें अपीलकर्ताओं ने विभिन्न पक्षकारों के पक्ष में 13 बिक्री विलेखों को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़े और इस तरह, ऊपर निर्दिष्ट उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की।

10. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, यहाँ उत्तरदाताओं ने विविध को प्राथमिकता दी। 2018 का सिविल आवेदन (अवमानना) सं. 121 और इसमें अपीलार्थियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की गई। उच्च न्यायालय ने अपने विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु तैयार किए:

“(i) क्या प्रत्यर्थी संख्या 3.1 से 3.4 और चौथे प्रत्यर्थी ने 2013 के विशेष सिविल आवेदन No.16266 में 2015 के सिविल आवेदन (निर्देश के लिए) No.11412 में पारित दिनांकित 14.10.2015 आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की है?

1075

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिजीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1076 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

((ii) क्या अवमानना कार्यवाही विलंब के आधार पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी है जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा तर्क दिया गया है या अवमानना आवेदन अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 20 के तहत निर्धारित सीमा के आधार पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी है? ((ग) कौन-सा आदेश?”

उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय:

11. हम एक उचित विचार देंगे कि उच्च न्यायालय ने अवमानना की कार्यवाही से कैसे निपटा। उच्च न्यायालय ने पहले उन विभिन्न बिक्री विलेखों पर ध्यान दिया जो अपीलार्थियों द्वारा 09.11.2015 और 30.10.2018 के बीच निष्पादित किए गए थे, जो उच्च न्यायालय को दिए गए वचन की जानबूझकर अवज्ञा कर रहे थे। विवरण इस प्रकार है:

	नहीं। सूचकांक पृष्ठ सं।	पार्टी का नाम	प्लॉट नं.	प्लॉट क्षेत्र	इंरेशन पर विचार करें	सूचकांक अनुसंधान
--	-------------------------	---------------	-----------	---------------	----------------------	------------------

1	157	जगदीश चुग	79	118.48	103115/-	56
2	158	रमा रानी	80	118.48	103115/-	56
3	159	प्रकाश कुंडू	199 ए.	118.48	8500/-	56
4	160	प्रकाश कुंडू	199 बी.	118.48	8500/-	56
5	161	प्रकाश कुंडू	200	118.48	8500/-	56
6	162	मफतलाल कालिदास एचयूएफ	122 बी (56)	118.48	8500/-	56
7	163	मफतलाल कालिदास एचयूएफ	122 सी (55)	118.48	8500/-	56
8	164	सुदेश डिंगरा	27	152	8500/-	72
9	165	शिल्पी रवि	27 ए.	152	8500/-	72
10	166	रोशन लाल	28	152	8500/-	72
11	167	सामी कुमार	176	118.48	8500/-	56
					282730/-	673

2 बिक्री विलेख बाद में किए गए/जोड़े गए						
1	5	त	व	1	4	2
2	1	ृ	9	9	9	0
	8	र	क		0	8
		ि	ा			-
		ल	न	2	0	5
		ो		6	0	3
		क	स	/	0	-
		र	ं	-	/	1
		ख		-		8
		म	्			
		य				
		म	ा			
		ा				
		ल	7			
		ी				
1	5	य	1	1	8	5
3	5	ो	7	1	5	6
	5	ज	5	8	0	8
		ी	.	0	7	7

“28. इस कार्यवाही में पहले समय पर सेवा में लगाए गए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान का प्रमाणिक मूल्य क्या होगा, इस पर भी इस न्यायालय का ध्यान गया है। यह इस न्यायालय द्वारा 29.01.2019 पर निम्नलिखित प्रभाव अधिनियम के लिए देखा गया: “वर्तमान कार्यवाहियों में, निजी प्रत्यर्थियों के नेतृत्व में समझौता किया गया है जिसमें बिना शर्त माफी मांगी जाती है और एक स्पष्ट बयान दिया जाता है कि इस तरह की सहमति दर्ज होने के बाद बिक्री विलेखों के निष्पादन की कार्रवाई के औचित्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं है; अर्थात् विषय भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए। एक अन्य हलफनामे में, यह पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने वकील को 1077 पर बयान देने का निर्देश दिया है

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1078

उनकी ओर से। इस प्रकार, उस कार्रवाई से कोई पलायन नहीं है जो रिट कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष किए गए वचन और बयान के जानबूझकर उल्लंघन का खुलासा करती है।”

(जोर दिया गया) 14. पैरा 31 में, उच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकन किया:

“31. तत्काल मामले में यह देखा जा सकता है कि चौथे प्रत्यर्थी के कहने पर, प्रत्यर्थी संख्या 3.1 से 3.4 और चौथे प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने 2013 के विशेष सिविल आवेदन No.16266 में एक बयान दिया था, जबकि विद्वान एकल न्यायाधीश 2015 के सिविल आवेदन (निर्देश के लिए) No.11412 पर निर्णय ले रहे थे और एक वचन दिया गया कि संपत्ति जिसमें प्रविष्टि की विषय वस्तु जो निर्विवाद रूप से सर्वेक्षण Nos.63 और 65 से संबंधित थी, उसे बेचा नहीं जाएगा और फिर भी उसे प्रत्यर्थी संख्या 3.1 से 3.4 द्वारा अपने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक चौथे प्रत्यर्थी के माध्यम से बेचा गया है। यदि यह वचन 2013 के विशेष सिविल आवेदन No.16266 में स्पष्ट रूप से उत्तरदाता नहीं दिया गया होता, जो 2015 के लेटर्स पेटेंट अपील (स्टाम्प) No.1196 में अपीलकर्ता थे, तो अपील को वापस नहीं लिया जाता जैसा कि दबाया नहीं गया था। आई. डी. 1 पर इस न्यायालय को दिया गया यह वचन ही है जिसने यहाँ आवेदकों को उक्त अपील को वापस लेने से रोका और यह न्यायालय को दिया गया यह गंभीर आश्वासन है जिसने उन्हें प्रतिवादी संख्या 3.1 से 3.4 और चौथे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए बयान को दर्ज करके अपील को वापस लेने के लिए मजबूर किया।”

(जोर दिया गया) 15. पैरा 33 में, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अवमानकर्ता सं. 3.1 से 3.4 ने चौथे अवमानक के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन पर विवाद नहीं किया था; उन्होंने बिक्री विलेखों के निष्पादन से इनकार नहीं किया था; उन्होंने बिक्री विलेखों के तहत लाभ प्राप्त करने से भी इनकार नहीं किया था; और उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि अवमानकर्ताओं द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि बिक्री विलेखों को निष्पादित किया जाना था क्योंकि बिक्री लेनदेन पहले ही पूरा हो चुका था, एक विचार के बाद था और इसका अभाव था

अच्छी बात है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

16. विवादित फैसले के पैरा 35 में, उच्च न्यायालय ने कहा कि अवमानकर्ताओं ने न केवल अदालत को दिए गए वचन का उल्लंघन किया है, बल्कि उन्होंने अपने लिए अनुचित लाभ भी उठाया है, अर्थात्, खरीददारों से अवमानकर्ताओं को दिए गए बिक्री प्रतिफल का स्वामित्व। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने पैरा 35 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

“35. तत्काल मामले में अवमानकर्ताओं ने न केवल न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन किया है, बल्कि अपने लिए अनुचित लाभ भी उठाया है, अर्थात् बिक्री का प्रतिफल खरीदारों से विक्रेताओं यानी अवमानकर्ताओं को दिया गया है। यहाँ तक कि ऊपर सारणीबद्ध कॉलम में संदर्भित बिक्री विलेखों में पाए जाने वाले पाठों के अनुसार, इसे रुपये के रूप में दर्शाया गया है- (11 बिक्री विलेखों के संबंध में); वर्ष में निष्पादित 2 बिक्री विलेखों के संबंध में- रुपये के रूप में दर्शाया गया है। सूचकांक मूल्य के अनुसार, 11 बिक्री विलेखों के संबंध में विचार राशि या उचित बाजार मूल्य Rs.67,38,432/- होगा, जबकि 2 बिक्री विलेखों के संबंध में सूचकांक मूल्य के अनुसार विचार या उचित बाजार मूल्य Rs.76,05,666/- होगा। अवमानकर्ता संख्या

3.1 से 3.4 के नेतृत्व में दिए गए जवाब में, प्रतिफल राशि के संबंध में एक फुसफुसाहट भी नहीं है। वे न तो यह तर्क देते हैं और न ही यह दलील देते हैं कि उक्त बिक्री विलेखों के तहत जो प्रतिफल उनके पास है, वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 3.1 से 3.4 के नेतृत्व में उत्तर के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की ओर से एफ. आई. डी. आई. डी. आई. आर. एफ. आई. का नेतृत्व करते हुए, शिकायतकर्ताओं द्वारा यह स्पष्ट रूप से तर्क दिया गया है कि अवमानकर्ताओं को धोखा देने और कानून की प्रक्रिया को खत्म करने के लिए, बचाव पक्ष के माध्यम से एक काल्पनिक याचिका पेश की गई है कि इस तरह की बिक्री के लिए वर्ष 2012 में 8,500/- रुपये का "नकद" लेनदेन हुआ था, जिसमें किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तव में, अवमानना सं. 3.1 द्वारा इस आशय का बचाव किया गया कि वह एक गृहिणी है, आवेदकों के नेतृत्व में प्रत्यर्पण याचिका में एक विशिष्ट याचिका दायर करके इनकार कर दिया गया है कि 1995 के विशेष दीवानी मुकदमे में दूसरे अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश, सूरत के समक्ष प्रतिपरीक्षा में प्रतिवादी सं. 4 ने बयान दिया है कि प्रतिवादी सं. 3.1 कपड़ा व्यवसाय में लगी हुई है और वह मैसर्स सूरत फैब्रिक कैप कंपनी लिमिटेड की निदेशक है और उसी सांस में उसने बयान दिया है कि परिवार के सभी सदस्यों को दिनांक 1079 के आदेश के बारे में पता था।

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1080 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

इस न्यायालय द्वारा पारित जहां तक प्रत्यर्थी सं. 3.2 के नेतृत्व में दिए गए उत्तर का जवाब देने का सवाल है, शिकायतकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी सं. 3.2 को दिनांकित आदेश के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था और यही जवाब देने वाले सं. 3.3 और 3.4 के नेतृत्व में दिए गए जवाब के खिलाफ दिए गए बयान में दिया गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि बिक्री विलेखों में दर्शाया गया बिक्री विचार प्रहसन है और न्यायालय के आदेश को दरकिनार करने के लिए वास्तविक मूल्य के मुकाबले कम विचार किया गया है। पैराग्राफ 6 (सी) में इस पहलू को उजागर करने के लिए शिकायतकर्ताओं ने प्रासंगिक समय पर तर्क दिया है कि विषय भूमि का जंत्री मूल्य 4,800/- रुपये प्रति वर्ग मीटर था। एमटीआर और बिक्री विलेख में दर्शाया गया प्रतिफल 8,500/- रुपये है। यह भी कहा गया है कि 118.80 वर्ग कि. मी. के लिए बिक्री लेनदेन के लिए विचार। एमटीआरएस। 152.00 वर्ग कि. मी. की सीमा तक बेची गई भूमि और उसके लिए एमटीआरएस। समान हैं और इसलिए शिकायतकर्ताओं का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से विषय संपत्ति को कम मूल्य पर बेच दिया है और इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। इस तथ्य को उजागर करने के लिए कि कथित कब्जा प्रमाण पत्र, जिस पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया है कि बिक्री लेनदेन वर्ष 2012 में पहले ही पूरा हो चुका था, जब दिनांकित बिक्री विलेख 09.02.2016 की तुलना में, यह स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि इन दोनों दस्तावेजों में दर्शाए गए सर्वेक्षण संख्या अलग और अलग हैं। इसलिए, यह तर्क देते हुए कि प्रकाश कुंडू के पक्ष में निष्पादित कब्जे की रसीदें और साथ ही रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नकद रसीदें जाली, फर्जी और मनगढ़ंत हैं और तथ्यों के विपरीत, शिकायतकर्ताओं ने उक्त दस्तावेजों को इस अदालत के विचार के दायरे से बाहर रखने की मांग की है।”

(जोर दिया गया) 17. पैरा 36 में, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अवमानकर्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था कि उन्होंने कार्यवाहियों में अपने हलफनामे में कहा था कि उन्होंने विषय संपत्ति को बेच दिया था, हालांकि वे पूरी तरह से परिचित थे और अदालत के समक्ष उनके द्वारा दिए गए वचन से अवगत थे कि वे मुख्य याचिका के निपटारे तक संपत्ति नहीं बेचेंगे।

18. पैरा 37 में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 4 (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक) दिनांक 28.08.2018 के नेतृत्व में एफ. आई. डी. एफ. आई. पर गौर किया। पैरा 37 इस प्रकार है:

“37. जबकि, आरोपी नं. 4 बिक्री विलेख के निष्पादन को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है, हालांकि, वह निम्नलिखित प्रभाव अधिनियम के लिए अपने एफ़ी डेविट दिनांक 28.08.2018 में गवाही देकर अज्ञानता का नाटक करने की कोशिश करता है:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“मैं कहता हूं कि हमारे खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि इस माननीय न्यायालय के दिनांक 14.10.2015 के आदेशों के विपरीत, हमने संपत्ति को उन व्यक्तियों को बेच दिया है जिनका उल्लेख अवमानना आवेदन के साथ संलग्न अनुक्रमित दस्तावेजों में किया गया है। मैं कहता हूं कि मुझे वास्तव में विश्वास था कि, पृष्ठ-157 पर अनुक्रमित दस्तावेजों में हमारे खिलाफ अवमानना

का आरोप लगाते हुए, मामले को अधिक उचित ठहराने की कोशिश किए बिना, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन सही तथ्यों को इंगित करूँ जिनके कारण मुझे विश्वास हुआ कि बिक्री पूरी हो गई थी। मैं कहता हूँ कि पृष्ठ-158 पर सूचकांक रजिस्टर की प्रति प्रशांतभाई हरधनभाई कोंडू के पक्ष में बिक्री के संबंध में प्रस्तुत की गई है, जो 09.02.2016 पर पंजीकृत है। मैं इसके साथ बिक्री विलेख की एक प्रति प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचकांक सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। हेरिटो और अनुलग्नक आर 1 के रूप में चिह्नित, दिनांकित 09.02.2016 के बिक्री विलेख की प्रति है। यह बहुत स्पष्ट है कि बिक्री 21.08.2012 पर पूरी की गई थी, लेकिन यह केवल पंजीकृत नहीं थी। बिक्री की अवज्ञा के अनुसार, लेन-देन पूरा हो गया है क्योंकि हमें विचार राशि प्राप्त हो गई है और हमने कब्जा सौंप दिया है। उक्त तथ्य का उल्लेख बिक्री विलेख में भी किया गया है।”

(जोर दिया गया) 19. पैरा 40 में, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अवमानना कार्यवाही में अवमानकर्ताओं को नोटिस जारी किए जाने के बाद भी, उन्होंने आगे भी अवमानना कार्य करना जारी रखा। पैरा 40 इस प्रकार है:

“40. अभियुक्तों ने अवमानना करना जारी रखा है। हम ऐसा इस कारण से कहते हैं कि शिकायतकर्ता संख्या 1.1 के नेतृत्व में दिनांक 30.10.2018 के बिक्री विलेख को संलग्न करते हुए दिनांक 06.04.2019 एफ. आई. का अतिरिक्त एफ. आई. डी. स्पष्ट रूप से उस आरोपी संख्या का खुलासा करेगा। 4 अपनी ओर से और अभियुक्त नं. 3. 1 से 3.4 तक 7 नंबर वाली दुकान बेची गई थी जिसका क्षेत्रफल 19.2 वर्ग किलोमीटर था। एमटीआरएस। भूमि धारक सर्वेक्षण सं. 63 में किस भूमि को इस न्यायालय को 14.10.2015 पर दिए गए वचन के माध्यम से नहीं बेचे जाने पर भी सहमति व्यक्त की गई थी। शिकायतकर्ता संख्या 1 के नेतृत्व में दिनांकित अतिरिक्त एफ. आई. डी. 1 दर्ज किया गया है जो 1081 के एक अन्य हिस्से का खुलासा करता है।

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1082 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

सर्वेक्षण संख्या 63 में 118.48 मापने वाली भूमि का निपटान दिनांक 25.07.2017 के बिक्री विलेख के माध्यम से किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 4, जिनसे अपने बयान (अनुलग्नक बी-2) में 1995 के विशेष दीवानी मुकदमा संख्या 130 में गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी, ने स्वीकार किया है कि वह उस अंतरिम आदेश से अवगत थे जिसमें उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। वास्तव में उन्होंने यह भी कहा है कि परिवार के सभी सदस्य दिनांकित 14.10.2015 के आदेश से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनका स्वीकारोक्ति इस प्रकार है:

“यह सच है कि मेरे अधिवक्ता श्री शिरीषभाई संजनवाला ने मेरे निर्देश पर मौखिक रूप से वचन दिया कि सर्वेक्षण संख्या 63 और 65 के लिए सी. एम. ए. के अंतिम परिणाम तक माजुरा की बिक्री नहीं की जाएगी। मुझे यह मौखिक रूप से याद नहीं है, लेकिन यह गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आवेदन संख्या 16266/13 में मेरे द्वारा मेरे अधिवक्ता श्री शिरीषभाई संजनवाला को दिए गए वचन के संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है, दिनांकित 14.10.2015 के आदेश को पढ़ने के बाद कि क्या कारण था कि उन्होंने मेरी ओर से आश्वासन दिया। मुझे अधिवक्ता श्री शिरीष संजनवाला से मिलने या उनसे चर्चा करने का अवसर नहीं मिला।”

(जोर दिया गया) 20. इसके बाद उच्च न्यायालय ने विचार किया कि क्या अवमानकर्ताओं द्वारा दी गई बिना शर्त माफी स्वीकार की जानी चाहिए और क्या उन्हें अवमानना कार्यवाही से दोषमुक्त किया जाना चाहिए या नहीं। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने क्रमशः पैरा 52 और 55 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

“52. अभियुक्त नं. प्रथम उपलब्ध अवसर पर चौथे प्रत्यर्थी को दी गई वकील की शक्ति को रद्द करने के लिए एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति की अपेक्षा के अनुसार कोई कदम नहीं उठाने के बावजूद, दूसरी ओर अवमानना की सूचना दिए जाने के बाद भी संपत्ति बेच देने के बाद, हमारा विचार है कि उनके द्वारा व्यक्त किए गए पश्चाताप या बिना शर्त माफी को वास्तविक और/या प्रामाणिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, अभियुक्त का आचरण और विशेष रूप से अभियुक्त नं. 3. 1 से 3.4 बिक्री विलेखों को रद्द न करना भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा कि उनके द्वारा व्यक्त किया गया पश्चाताप या पश्चाताप वास्तविक नहीं है और माफी का प्रदर्शन करके अवमानना की कार्यवाही को रोकने के लिए किया गया है और यह तर्क देते हुए कि आरोपी नहीं है, नाराज़गी जताने की कोशिश की गई है।

3.1 और 3.2 गृहिणियों को गुस्सा करने या सुरक्षात्मक छत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और उन्हें इस तरह के परोपकार के विस्तार के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्तियों द्वारा अज्ञानता का नाटक करके न्याय के प्रशासन की शुद्ध धारा प्रदूषित हो जाएगी और इस तरह हमारा विचार है कि उनसे लोहे के हाथों से निपटा जाना चाहिए।

xxx

xxx

xxx

55. हाथ में मौजूद तथ्यों को लागू करते हुए, जैसा कि हमने पहले ऊपर देखा है, कि आरोपी संख्या 3.1 से 3.4 अपने मामले को चरण-दर-चरण सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और बिना किसी वास्तविक पश्चाताप के माफी मांग रहे हैं और यह दिल से नहीं है, बल्कि उनके अवमाननापूर्ण कार्य से होने वाले परिणामों को रोकने के लिए एक मौखिक सहानुभूति के रूप में कहा गया है, माफी का आरोप लगाया गया है। यदि वास्तविक पश्चाताप होता, तो वे अवमानना की सूचना दिए जाने पर आरोपी नं.4. हालाँकि, उन्होंने ऐसा करने के लिए नहीं चुना है। दूसरी ओर, उन्होंने उसे अपने एजेंट के रूप में कर्तव्यों का पालन जारी रखने की अनुमति दी है और इससे लाभ प्राप्त किया है, जिससे पता चलता है कि उनके द्वारा व्यक्त कोई वास्तविक पश्चाताप नहीं है जो अदालतों की चेतना को संतुष्ट करेगा।

(जोर दिया गया) 21. इसके बाद उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा कि क्या अवमानना की कार्यवाही पर समय की पाबंदी थी। उच्च न्यायालय ने अधिनियम 1971 की धारा 20 को देखा और यह विचार रखा कि कार्यवाही का कारण प्रकृति में बार-बार हो रहा था और गलत जारी रहा था। शुरू की गई कार्यवाही को अधिनियम 1971 की धारा 20 के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया था।

22. अंतिम में, उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि उस तारीख को क्या हुआ था जब अवमानकर्ता अपने खिलाफ लगाए गए आरोप का जवाब देने के लिए अदालत में मौजूद थे। उच्च न्यायालय ने पैरा 61 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

“इस प्रकार, इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा अवमानकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने और यह जवाब देने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ आरोप क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। उसी के जवाब में, अवमानकर्ताओं द्वारा 24.12.2018 पर एक हलफनामा दायर किया गया है जिसमें अदालत को दिए गए वचन की अवज्ञा और उल्लंघन को स्वीकार किया गया है। चौथे प्रत्यर्थी के शब्दों में, प्रवेश निम्नलिखित प्रभाव को पढ़ता है:

1083

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1084

"2. मुझे ईमानदारी से खेद है कि बिक्री विलेखों का निष्पादन मेरी ओर से विद्वान वकील द्वारा दिए गए बयान का उल्लंघन था। मैं स्पष्ट समझ के साथ ईमानदारी से बिना शर्त माफी मांगता हूँ कि बयान का उल्लंघन हुआ है। मेरा निवेदन है कि बिक्री विलेखों के निष्पादन की कार्यवाही के औचित्य की कोई गुंजाइश नहीं है जो मैंने समझौते-धारकों द्वारा बनाए गए दबाव में की थी। मैं आपके प्रभुओं से अनुरोध करता हूँ कि यदि वे उचित समझते हैं तो मेरी माफी स्वीकार करें।"

(जोर दिया गया) 23. उच्च न्यायालय ने अंततः अपीलार्थियों को वचन की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया और उन्हें तदनुसार दंडित किया।

24. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपीलों के साथ इस न्यायालय के समक्ष हैं।

नागरिक आवेदन संख्या में अपीलकर्ताओं के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ। **2022 का 5041**

25. 2022 की सिविल अपील संख्या 5041 के अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी उपस्थित हुए। श्री रोहतगी ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया:

(क) अपीलार्थी संख्या 1 और 2 को इस बारे में कोई जानकारी या उचित जानकारी नहीं थी कि राजस्व प्राधिकरणों या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में क्या हो रहा था, क्योंकि अपीलार्थियों ने बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी (संबंधित अपील के अपीलार्थी) को अपने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में नियुक्त किया था। पावर ऑफ अटॉर्नी धारक विषय भूमि से संबंधित

मुकदमे की देखरेख करता था और अपीलार्थी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में किसी भी तरह से शामिल नहीं थे। बिक्री विलेखों पर अपीलार्थियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे क्योंकि उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा निष्पादित किया गया था।

(ख) उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में भौतिक रूप से गलती की कि अपीलकर्ताओं ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया था कि वे उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए वचन के बारे में पूरी तरह से अवगत और अवगत थे। यह दिनांकित 07.10.2018, 28.10.2018 और 24.12.2018 के तीनों एफ़ी डेविटों के अवलोकन में एक स्पष्ट तथ्यात्मक त्रुटि है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

अपीलार्थियों के नेतृत्व में क्रमशः एफ. आई. इसके विपरीत कहता है कि उन्हें दिनांकित 14.10.2015 के आदेश के बारे में पता नहीं था।

(ग) उच्च न्यायालय को पहली बार में की गई बिना शर्त और वास्तविक माफी को स्वीकार करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए गलती की कि माफी देर से मांगी गई थी।

(घ) अधिनियम 1971 की धारा 12 में न्यायालय की अवमानना के लिए सजा निर्धारित की गई है। उक्त धारा के परंतुक में कहा गया है कि 'अभियुक्त को आरोपमुक्त किया जा सकता है या अदालत की संतुष्टि के लिए माफी मांगने पर सजा दी जा सकती है'। इसके अलावा, उक्त परंतुक के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि "माफी को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि यह योग्य या सशर्त है यदि आरोपी इसे वास्तविक बनाता है।"

(ई) उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करने में एक गंभीर त्रुटि की कि बिक्री विलेख दिनांक 1 के आदेश से पहले ही पूरा कर लिया गया था और केवल बिक्री विलेखों का औपचारिक पंजीकरण बचा था।

(च) उच्च न्यायालय ने यह दर्ज करने में त्रुटि की कि अपीलार्थियों को अवमानना का नोटिस जारी किए जाने के बाद भी संपत्तियों को बेचा गया था।

26. उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने निम्नलिखित मामले कानून पर भरोसा रखा:

(i) राम नारंग बनाम रमेश नारंग और दूसरा (2006) 11 एस. सी. सी.

114;

((ii) अनिल के. सुराना और एक अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, (2007)

10 एससीसी 257;

(iii) भारत स्टील ट्यूब लिमिटेड बनाम आईएफसीआई लिमिटेड, (2010) 14 एससीसी

77; और

(iv) अभिषेक कुमार सिंह बनाम जी. पटनायक और अन्य, (2021) 7

एससीसी 613।

27. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रार्थना की कि उनकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाए।

1085

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1086

28. 2022 की सिविल अपील संख्या 5041 में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मिहिर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

(क) उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा इस आधार पर मांगी गई माफी को स्वीकार नहीं करने में गलती की है कि यह पहली बार में नहीं दी गई थी। फॉर्म-1 में नोटिस 23.04.2018 पर जारी किया गया था। नोटिस जारी किए जाने के बाद, अपीलार्थी के दिनांक 24.08.2018 वाले पहले शपथ पत्र में एक बिना शर्त माफी शामिल है। एक और एफ़ी डेविट दिनांकित 24.12.2018 भी बिना शर्त माफी माँगता है। क्षमा याचना वास्तविक होने के कारण, जैसा कि मामले के तथ्यों से स्पष्ट है और पहली बार में प्रस्तुत की गई है, न्यायालय द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए थी। उच्च न्यायालय ने पैरा 49 (iv) में एक तथ्यात्मक रूप से गलत निर्णय दिया कि पहली बार में कोई बिना शर्त माफी नहीं मांगी गई थी ताकि अभियुक्त के कार्यों को जानबूझकर या जानबूझकर नहीं किया गया हो। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश के पैरा 38 में यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि प्रथम एफ़ी डेविट दिनांक 28.08.2018 में बिना शर्त माफी नहीं है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। उक्त एफ़ी डेविट दिनांक 28.08.2018 ने बिना शर्त माफी मांगी।

(ख) वास्तव में, अवमानना की कार्यवाही बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि दिनांक 1 के आदेश में अपीलार्थी की ओर से दर्ज किया गया बयान न तो न्यायालय का आदेश है और न ही न्यायालय को दिया गया वचन है और इसलिए, इसका कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है, जो अधिनियम 1971 की धारा 2 (बी) के तहत विचार की गई दीवानी अवमानना के बराबर है। यह स्वयं स्पष्ट है कि बयान दूसरे पक्ष के लिए एक आश्वासन है न कि अदालत के लिए एक वचन। इस तरह के बयान का उल्लंघन विरोधी पक्ष द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए एक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है जिसे विधिवत गठित कार्यवाही में निर्णय लेना होगा, लेकिन यह अवमानना के लिए कार्यवाही को आमंत्रित नहीं करेगा क्योंकि यह न तो अदालत का आदेश है और न ही अदालत के लिए एक वचन है। यह भेद न्यायालयों द्वारा सर्वविदित और स्वीकार किया गया है और अवमानना आवेदन को केवल इस आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं होने के रूप में खारिज किया जाना चाहिए था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

(ग) उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि दिनांक 1 के आदेश में दर्ज बयान का उल्लंघन (यह मानते हुए कि इसे अधिनियम 1971 की धारा 2 (बी) के तहत एक उपक्रम माना जाता है) एक जानबूझकर और जानबूझकर उल्लंघन था, जिसमें निम्नलिखित तथ्यों की अनदेखी की गई थी:

(i) न्यायालय ने बिक्री की आवश्यकता के बारे में अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर अविश्वास करने में गलती की है क्योंकि विषय हस्तांतरण 14.10.2015 से बहुत पहले कब्जे की प्राप्ति के माध्यम से विचार के पूर्ण भुगतान और कब्जे को सौंपने के साथ समाप्त हो गया था और इसलिए, हस्तांतरण 14.10.2015 पर दर्ज विवरण द्वारा कवर नहीं किए गए थे। उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विषय बिक्री के संबंध में कब्जे की रसीदें, भुगतान रसीदें और बैंक खाता विवरण के उद्धरण जैसे दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए गलती की कि यह स्थापित करने या प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि संपत्ति वास्तव में वर्ष 2012 में ही बेची गई थी। उच्च न्यायालय ने पैरा 35 में यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि बचाव पक्ष के माध्यम से एक काल्पनिक याचिका दायर की गई थी कि नकद लेनदेन वर्ष 2012 में बिक्री के लिए किया गया था जिसमें किसी तारीख का उल्लेख नहीं है।

((ii) उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि उपरोक्त दस्तावेज कथित रूप से मनगढ़ंत थे और केवल आयकर विवरणी ही सबसे अच्छा सबूत हो सकता है।

(iii) उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि विवादित बिक्री लेनदेन केवल 1521 वर्ग किलोमीटर के थे। एमटीआरएस। सर्वेक्षण सं। 63 का क्षेत्रफल 33,790 वर्ग किलोमीटर है। एमटीआरएस। और कि सर्वेक्षण सं। 65 का क्षेत्रफल 31,095 वर्ग किलोमीटर है। एमटीआरएस। यह बिना बेचे और खाली था जो स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों द्वारा समझे गए बयान के पालन को दर्शाता है और अपीलार्थियों के स्पष्टीकरण का समर्थन करता है कि 118 वर्ग किलोमीटर के छोटे भूखंडों की विषय बिक्री। एमटीआरएस। प्रत्येक को औपचारिक रूप से समाप्त किया जाना था क्योंकि वास्तविक हस्तांतरण आईडी 1 से कई साल पहले हुआ था और भूखंडों के विकास में आवंटनकर्ताओं को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया जा रहा था और इस तरह के हस्तांतरण कभी भी 1087 नहीं थे।

14.10.2015 के विवरण के तहत कवर करने का इरादा है जो केवल भविष्य के हस्तांतरण के लिए काम करेगा।

(iv) उच्च न्यायालय ने इस बात की अनदेखी करते हुए गलती की कि अवमानना कार्यवाही में आवश्यक सबूत का मानक, एक अर्ध-आपराधिक कार्यवाही होने के नाते, एक आपराधिक कार्यवाही है और उल्लंघन को उचित संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्य उचित संदेह से परे यह स्थापित नहीं करते हैं कि अदालत के आदेश, या अदालत को दिए गए बयान या वचन का जानबूझकर उल्लंघन या अवज्ञा की गई थी। अवमानना की शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और सबूत के आवश्यक मानक को पूरा करने के बाद ही किया जाना चाहिए।

(v) उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही करने में गलती की कि अपीलकर्ताओं ने अवमानना करना जारी रखा और इस संबंध में विवादित फैसले के पैरा 26 में तालिका के क्रमवार आई. डी. 1 और 13 में बताए गए लेनदेन पर भरोसा किया। किसी दुकान के सीरियल No.12 में कथित लेन-देन, कथित रूप से 30.10.2018 का, विषय भूमि S.No.63 और 65 का हिस्सा नहीं है, जिसके संबंध में 14.10.2015 दिनांकित आदेश पारित किया गया था; और सीरियल No.13 पर लेन-देन 25.7.2017 का है, इसलिए यह अवमानना याचिका (FI के नेतृत्व में 12.01.2018) के अंतिम लिंग के बाद की तारीख का नहीं है।

(घ) उच्च न्यायालय ने उस संदर्भ और पृष्ठभूमि तथ्यों को नजरअंदाज करने में गलती की है जिसमें बयान दिया गया था और उसी के आलोक में बयान में क्या अर्थ और शामिल किया गया था। (ई) न्यायालय ने अधिनियम 1971 की धारा 13 की आवश्यकता की अनदेखी की है क्योंकि अपीलार्थी के आचरण ने किसी भी तरह से न्याय के उद्देश्य में बाधा नहीं डाली है। जैसा कि इस द्वारा आयोजित किया गया है

मर्रे एंड कंपनी बनाम में न्यायालय अशोक के. नेवटिया एंड अदर, (2000)

2 एस. सी. सी. 367 (पैरा 19 से 22), धारा 13 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि यह पर्याप्त नहीं है कि अदालत की कुछ तकनीकी अवमानना होनी चाहिए, लेकिन यह दिखाया जाना चाहिए कि अवमानना का कार्य अन्यथा न्याय के उचित पाठ्यक्रम में काफी हद तक हस्तक्षेप करेगा, जिसे "न्याय के उचित प्रशासन" के बराबर माना गया है।

न्याय "।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

(च) उच्च न्यायालय ने सिविल अवमानना के लिए कारावास की सजा देने में कोई कारण बताए बिना गलती की कि इस तरह के अपवाद को और अधिक विशेष रूप से निम्नलिखित की अनदेखी करते हुए क्यों बनाया जाना चाहिए:

(i) धारा 12 (3) की बारीकी से जांच से संकेत मिलता है कि विधायिका का इरादा था कि दीवानी अवमानना के मामले में अकेले दंड की सजा दी जानी चाहिए, सिवाय इसके कि अदालत यह मानती है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए कारावास की सजा भी पारित करना आवश्यक है। एक चरम सजा देने से पहले, न्यायालय को उचित दिमाग लगाने के बाद विशेष कारण बताना चाहिए। फैसले में इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई औचित्य या कारण नहीं दिया गया है कि मामले में कारावास उचित है।

((ii) उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के वास्तविक अधिकारों की अनदेखी करने में गलती की, जिसने यह स्थापित किया होगा कि दिनांक 1 के आदेश में दर्ज बयान का कोई जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया था और किसी भी मामले में, निश्चित रूप से कारावास को उचित नहीं ठहराएगा। विशेष रूप से, न्यायालय ने इस बात की अनदेखी की है कि अपीलकर्ता ने पहली बार आई. डी. 3 पर अपनी बिना शर्त माफी मांगी; माफी से विचलित हुए बिना आई. डी. 4 पर तुरंत आवश्यक दस्तावेजों के साथ लेन-देन की व्याख्या की; याचिका के अंतिम चरण तक भूमि के समतुल्य क्षेत्र को खुला और खाली रखने के लिए प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय दिनांक आई. डी. 1 के माध्यम से; कि पहले के एफ. आई. डी. डी. डी. डी. डी. डी. डी. डी. डी. डी. डी.

30. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जाए और विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाए।

जिम्मेदारों के स्वयं के बारे में सुझाव

31. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने यहां जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में कानून की किसी भी त्रुटि की बात न करने में कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती है।

32. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

(क) उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश में अभिलिखित न्यायालय को विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिया गया आश्वासन अधिनियम 1971 की धारा 12 और 13 के अनुसार एक स्पष्ट वचन है। इसे अदालत को दिए गए एक स्पष्ट वचन के रूप में देखा जाना चाहिए और इसे संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी माना जाना चाहिए। यदि यह वचन नहीं दिया गया होता तो 2015 की एल. पी. ए. (स्टाम्प) संख्या 1196 में अपील करने वाले प्रत्यर्थियों ने अपील को वापस नहीं लिया होता जैसा कि दबाया नहीं गया था। इसके अलावा, एल. पी. ए./उत्तरदाताओं के अपीलकर्ताओं ने उक्त वचन के कारण 2013 के एस. सी. ए. संख्या 16266 में कोई और आदेश आमंत्रित नहीं किया।

(ख) वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिया गया वचन। स्पष्ट रूप से अधिनियम 1971 की धारा 2 (बी) के अंतर्गत आता है, "कि इस प्रविष्टि और याचिका की विषय वस्तु संपत्ति को तब तक नहीं बेचा जाएगा जब तक कि मुख्य याचिका की सुनवाई और निर्णय नहीं हो जाता। विद्वान वकील द्वारा दिया गया वचन-पत्र पूरी तरह से अपीलार्थियों के लिए बाध्यकारी है।

1091

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1092

(ग) इस तरह के स्पष्ट वचन के बावजूद, अपीलकर्ताओं ने 2015 और 2018 के बीच भूखंडों को बेच दिया। यदि अपीलार्थी कुछ मजबूर करने वाली परिस्थितियों में भूखंडों को बेचना चाहते थे, तो वे आदेश में संशोधन या बदलाव के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते थे, जो उन्हें नहीं लगता था। इसके अलावा, अवमानना के एक स्पष्ट निरंतर कार्य के रूप में, बिक्री विलेखों के निष्पादन के बाद भी अपीलार्थी उक्त पहलू को उच्च न्यायालय के ध्यान में लाने में विफल रहे।

(घ) अवमानना कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भी अपीलार्थी अवमानना करते रहे। उन्होंने दुकान को नं. के साथ बेच दिया। 7 30.10.2018 यानी अवमानना का नोटिस जारी होने के 9 महीने बाद। उन्होंने भूमि धारक सर्वेक्षण संख्या 65 को भी रुपये की राशि के साथ 09.09.2021 पर बेच दिया। 51,93,00,000/- जो उच्च न्यायालय की अवमानना कार्यवाही के रिकॉर्ड में भी है।

(ङ) अपीलकर्ताओं ने वर्ष 2012 (आयकर विवरण, बैंक विवरण आदि) में खरीदारों को अपने कब्जे में रखने के अपने मामले के समर्थन में कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। उन्होंने जो नकद रसीद प्रस्तुत की है, वह एस. के. इंडस्ट्रीज सर्विस सोसाइटी द्वारा जारी की गई है, न कि वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा और यह भी कि वे सभी दस्तावेज अप्रमाणित, जाली और मनगढ़ंत हैं। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश (पृष्ठ 38 पर पैरा 35) में इस तथ्य पर विधिवत ध्यान दिया है। कानून के अनुसार, बिक्री को उस तारीख को पूरा किया गया माना जाता है जब बिक्री विलेख पंजीकृत किया जाता है, जो तत्काल मामले में 2013 के एस. सी. ए. संख्या 16266 में वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए वचन के बाद स्वीकार किया जाता है जैसा कि उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश में दर्ज किया गया है।

(च) अपीलार्थियों द्वारा दी गई माफी एक प्रहसन है। अपीलार्थियों की ओर से माफी पहली बार में नहीं आई। यदि उन्हें वास्तव में खेद था, तो उन्हें अवमानना कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निष्पादित बिक्री विलेखों को रद्द कर देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया है। यह केवल वर्तमान कार्यवाही में है कि उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने भूखंड धारकों को पत्र भेजकर बिक्री विलेखों को रद्द करने का प्रयास किया है। इस प्रकार, उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने उच्च के आदेश का पालन करने के लिए एक कार्य किया है।

अदालत में, लेकिन इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है कि नोटिस कब और किस तरीके से भेजे गए या निष्पादित किए गए थे, यानी डाक या ईमेल या कूरियर आदि के माध्यम से। अपीलार्थियों के इस तरह के संदिग्ध आचरण से पता चलता है कि अवमानना करने और कोई पछतावा नहीं दिखाने के बावजूद, वे अभी भी ऐसे दस्तावेज पेश करके इस न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके नंगे पढ़ने से झूठे, अविश्वसनीय और मनगढ़ंत प्रतीत होते हैं।

(छ) अपीलों की सुनवाई के दौरान, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जोशी ने सर्वेक्षण संख्या 65 की भूमि को अलग रखने के लिए एक वैकल्पिक उपाय का सुझाव दिया था, लेकिन वास्तव में, अपीलकर्ताओं ने वर्ष 2021 में अवमानना कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भी उसी भूमि को बेच दिया है। इस प्रकार, अवमानकर्ताओं ने इस तरह के झूठे बयान देकर इस अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है।

33. अपनी उपरोक्त दलीलों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने टी. रवि (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

34. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रार्थना की गई थी कि दोनों वैधानिक अपीलों में कोई योग्यता नहीं होने के कारण उन्हें खारिज किया जा सकता है।

नागरिक आवेदन संख्या में अपीलकर्ताओं के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ। **2023 का 4869**

35. अपीलार्थी अवमानकर्ताओं से भूखंडों के खरीदार होते हैं। खरीदारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अवमानकर्ताओं द्वारा उनके मुवक्किलों के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेखों को अवैध या अमान्य घोषित करने में गंभीर त्रुटि की है। श्री दीवान के अनुसार, इस समय यह मानते हुए कि स्थानांतरण अवमानकर्ताओं द्वारा दिए गए वचन की जानबूझकर अवज्ञा में था, इस तरह के स्थानांतरण अमान्य हस्तांतरण नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, मुकदमे की संपत्ति का हस्तांतरण शुरू से ही शून्य नहीं है। वह तर्क देगा कि उसके ग्राहक बिना किसी सूचना के संपत्ति के वास्तविक खरीदार हैं। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को इक्विटी को अधिक संतुलित करना चाहिए था, विशेष रूप से जब अवमानकर्ताओं ने शिकायतकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अन्य वैकल्पिक भूमि को पट्टे पर दे दिया था।

36. यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय को अवमानना कार्यवाही में खरीदारों की उपस्थिति पर जोर देना चाहिए था। बिना कोई 1093 दिए

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1094

खरीदारों को सुनने के अवसर पर, उच्च न्यायालय को बिक्री लेनदेन को अमान्य घोषित नहीं करना चाहिए था। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं ने संपत्तियों को आगे हस्तांतरित कर दिया है और यह उन्हें ऐसे बाद के खरीदारों द्वारा आगे की दीवानी और आपराधिक कार्यवाही के लिए असुरक्षित बना देगा। 37. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री दीवान ने प्रार्थना की कि यह न्यायालय इक्विटी को झुका सकता है और बिना किसी सूचना के संपत्ति के वास्तविक खरीदारों को मूल्य के लिए सुरक्षित कर सकता है।

38. श्री श्याम दीवान द्वारा प्रचार की गई उपरोक्त प्रस्तुति, उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने सुझाव दिया कि अपीलकर्ताओं (खरीदारों) ने संपत्तियों को आगे हस्तांतरित कर दिया है और आज की तारीख तक उनकी विषय संपत्तियों में कोई रुचि नहीं है।

विश्लेषण

39. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है?

संबंधित न्यायनिर्णयन का अभ्यास करने वाले शासकों की सरकार

40. अदालत की अवमानना के मामले में अदालत द्वारा लागू अनुशासन का उद्देश्य अदालत या न्यायाधीश की गरिमा को सही साबित करना नहीं है, बल्कि न्याय के प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप को रोकना है।

41. न्याय के मार्ग में कोई भी हस्तक्षेप कानून की महानता के लिए एक कारण है और हस्तक्षेप का आचरण अदालत की अवमानना के रूप में दंडनीय है। जनहित की मांग है कि न्यायिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और न्यायिक निर्णय का प्रभाव नहीं होना चाहिए।

पूर्व-खाली या अव्यवस्थित। (रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मालिकों ने बताया)

(1988) 4 एस. सी. सी. 592 में। 42. यदि कोई पक्ष, जो न्यायालय के निर्णय/आदेश के बारे में पूरी तरह से जानता है, न्यायालय के आदेश के परिणामों और निहितार्थ के बारे में सचेत और जागरूक है, तो उसका उल्लंघन करते हुए कार्य करता है, यह माना जाना चाहिए कि अवज्ञा जानबूझकर है। न्यायालय की अवमानना स्थापित करने के लिए, यह साबित करना पर्याप्त है कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

आचरण जानबूझकर किया गया था, और यह कि अवमानकर्ता को उन सभी तथ्यों के बारे में पता था जो इसे वचन का उल्लंघन बनाते थे।

43. किसी व्यक्ति को नागरिक अवमानना करने के लिए अभिनिर्धारित करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: (i) न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया होनी चाहिए; (ii) न्यायालय के ऐसे निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की अवज्ञा होनी चाहिए; और (iii) न्यायालय के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की ऐसी अवज्ञा जानबूझकर होनी चाहिए। [पटेल रजनीकांत]

धुलाभाई और एक अन्य बनाम पटेल चंद्रकांत धुलाभाई और अन्य,

(2008) 14 एस. सी. सी. 561 में सूचित। 44. न्यायालय को निर्णय की त्रुटियों के लिए सभी भत्ते देते हुए यथासंभव बड़ी सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। यह केवल तभी होता है जब आपत्तिजनक आचरण का एक स्पष्ट मामला, जो अन्यथा समझाने योग्य नहीं है, उत्पन्न होता है कि अवमानकर्ता को दंडित किया जाना चाहिए। अवमानना के कानून के तहत सजा की मांग तब की जाती है जब चूक जानबूझकर और किसी के कर्तव्य की अवहेलना और अधिकार की अवहेलना में हो। अवमानना कार्यवाही प्रकृति में अर्ध-आपराधिक होती है, और सबूत का मानक अन्य आपराधिक मामलों की तरह ही होता है। कथित अवमानकर्ता सभी सुरक्षा उपायों/अधिकारों के संरक्षण का हकदार है, जिसमें शामिल हैं -

सन्देह का लाभ। [कंवर सिंह सैनी बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट की]

(2012) 4 एस. सी. सी. 307। 45. न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता कानून द्वारा शासित समाज के लिए सर्वोपरि है। अन्यथा, लोकतंत्र की इमारत ही टूट जाती है और अराजकता हावी हो जाती है। अधिनियम 1971 का उद्देश्य उस व्यक्ति को सही करना है जो मानदंड से भटक रहा है और कानून का उल्लंघन करने/खुद को कानून मानने की कोशिश कर रहा है। इसका उद्देश्य न्यायालय के आदेशों/न्यायालय को दिए गए वचन की अवज्ञा करने में गलती करने वालों को अनुशासित करके न्याय के प्रशासन में लोगों का विश्वास हासिल करना है।

46. इस न्यायालय ने कई मामलों में 1971 के अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग के वास्तविक उद्देश्य को समझाया है। मृत्युंजय दास (ऊपर) में, यह अभिनिर्धारित किया गया है:

“13. हालाँकि, मामले को आगे बढ़ाने से पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग अपेक्षाकृत सतर्क होना चाहिए और अवमाननापूर्ण आचरण के वास्तविक प्रभाव को संबोधित करने के बाद इसका सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। अदालत को अन्यथा 1095 होना चाहिए।

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिजीजड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1096 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि आचरण न्याय में बाधा के समान है जिसकी अनुमति दी जाए तो यह हमारे समाज में भी व्याप्त हो जाएगा (मुर्रे एंड कंपनी बनाम। अशोक के. नेवटिया [(2000) 2 एस. सी. सी. 367:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 473]) यह एक विशेष अधिकार क्षेत्र है जो विधि अदालतों को किसी अपराधी को उसके अवमाननापूर्ण आचरण या कानून की महिमा में बाधा डालने के लिए दंडित करने के लिए दिया जाता है। यह इस संदर्भ में है कि मर्रे मामले [(2000) 2 एस. सी. सी. 367 में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 473] जिसमें हम में से एक (बनर्जी, जे.) पार्टी थी, पर ध्यान देने की आवश्यकता है: (एस. सी. सी. पी. 373, पैरा 9)

“अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य अदालतों की महिमा और गरिमा को बनाए रखना है क्योंकि लोगों के मन में इस तरह की महिमा की छवि को विकृत नहीं किया जा सकता है। अदालतों द्वारा प्रदत्त सम्मान और अधिकार एक आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी गारंटी है और यदि न्यायपालिका के प्रति सम्मान को कम किया जाता है तो समाज का पूरा लोकतांत्रिक ताना-बाना ध्वस्त हो जाएगा। यह सच है कि न्यायपालिका जो करती है उसके लिए न्यायपालिका को लोगों द्वारा आंका जाएगा, लेकिन किसी भी तरह के हस्तक्षेप की स्थिति में, जिसे दूर से भी कानून की महिमा को प्रभावित करने वाला कहा जा सकता है, समाज न्यायपालिका और कानूनी अदालतों में विश्वास खोने के लिए बाध्य है और इस प्रकार आम तौर पर लोगों का विश्वास और विश्वास खो देगा।”

47. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अधिनियम **1971** के तहत शक्तियों के दायरे और किसी पक्ष को दंडित करते समय पालन किए जाने वाले सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए कहा:

“28. उपरोक्त प्रावधान के विश्लेषण से पता चलता है कि धारा 12 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि स्थापित अवमानना के मामले में अवमानना करने वाले को दंडित किया जा सकता है:

(क) सिविल जेल में निरोध द्वारा साधारण कारावास के साथ; या (ख) दंड के साथ; या

((ग) दोनों के साथ। धारा 12 की उप-धारा (2) को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि अधिनियम अदालत पर अधिक सजा न देने के लिए प्रतिबंध लगाता है।

उप-धारा (1) के अधीन विहित दंडादेश। धारा 12 की उप-धारा (3) की बारीकी से जांच से पता चलता है कि विधायिका का इरादा था कि दीवानी अवमानना के मामले में अकेले दंड की सजा दी जानी चाहिए, सिवाय इसके कि अदालत यह मानती है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए कारावास की सजा भी पारित करना आवश्यक है। पुष्पाबेन बनाम नारदास वी. बडियानी [(1979) 2 एस. सी. सी. 394 के मामले में अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत सजा के अधिरोपण से निपटना: 1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 511] इस न्यायालय ने राय दी: (एस. सी. सी. पी. 396, पैरा 6)

“6. निकाले गए खंड की एक करीबी और सावधानीपूर्वक व्याख्या इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है कि विधायिका का इरादा था कि सामान्य परिस्थितियों में अकेले दंड की सजा दी जानी चाहिए। हालाँकि, कानून न्यायालय को कारावास की सजा देने की विशेष शक्ति प्रदान करता है यदि वह सोचता है कि न्याय के उद्देश्यों की आवश्यकता है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा कारावास की चरम सजा पारित करने से पहले, उसे अपने दिमाग के उचित अनुप्रयोग के बाद विशेष कारण देने चाहिए कि किसी विशेष स्थिति में केवल कारावास की सजा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, कारावास की सजा एक अपवाद है जबकि फिने की सजा नियम है।”

×××

×××

×××

34. सजा का उद्देश्य उपचारात्मक और सुधारात्मक दोनों होने के कारण, ये जबरदस्ती एक व्यक्तिगत शिकायतकर्ता को उसके उपचार को लागू करने में सहायता करने के लिए हैं और नागरिक अवमानना को दंडित करने के लिए सार्वजनिक नीति का एक तत्व भी है, क्योंकि न्याय के प्रशासन को कमजोर किया जाएगा यदि किसी भी अदालत के आदेश की अवहेलना दंड से मुक्ति के साथ की जाती है। कुछ परिस्थितियों में, आदेश का अनुपालन अवमानना शक्ति के माध्यम से जबरदस्ती का सहारा लिए बिना

सुरक्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक राशि का भुगतान करने के आदेश की अवज्ञा का प्रभावी रूप से प्रतिवाद करने वाले की कमाई को संलग्न करके प्रतिकार किया जा सकता है। इसी तरह, संपत्ति के हस्तांतरण के विशिष्ट निष्पादन के आदेश का पालन करने में विफलता के लिए चूककर्ता के व्यक्ति को जेल में डालना, अदालत द्वारा यह निर्देश भी दिया जा सकता है कि हस्तांतरण एक नियुक्त व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाए। किसी वचन की अवज्ञा को उसी तरह से जेल में डालने के अलावा अन्य प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जा सकता है, उदाहरण के लिए जहां वचन का उल्लंघन मकान मालिक-किरायेदार विवाद में संपत्ति का कब्जा देने के लिए किया जाता है। 1097 के अलावा

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1098

अवमानना करने वाले को दंडित करने से लेकर, अदालत कानून की महिमा बनाए रखने के लिए पुलिस बल को कब्जे की वसूली के लिए उपयोग करने का निर्देश दे सकती है और अवमानना करने वाले पर लागत, अनुकरणीय या अन्यथा का बोझ डाल सकती है।

× × ×

× × ×

× × ×

36. यह तय करने में कि क्या अवमानना कारावास के योग्य होने के लिए पर्याप्त गंभीर है, अदालत न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप की संभावना और दोषी के दोष को ध्यान में रखेगी। जिस इरादे से कार्य की शिकायत की गई है, वह यह निर्धारित करने में एक भौतिक कारक है कि किसी दिए गए मामले में कौन सी सजा उचित होगी।

× × ×

× × ×

× × ×

42. न्यायालय की अवमानना एक विशेष अधिकार क्षेत्र है जिसका उपयोग संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए जब भी कोई कार्य न्याय के प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या जो इसके पाठ्यक्रम में बाधा डालता है या न्यायिक संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास को हिलाता है। इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब भी किया जा सकता है जब कानून की महिमा या अदालतों की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की शिकायत की गई हो। अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य अदालतों की महिमा और गरिमा को बनाए रखना है। यह "जुरी, न्यायाधीश और जज्जाद" को मिलाकर एक असामान्य प्रकार का अधिकार क्षेत्र है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालत मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों के बीच किसी भी दावे पर निर्णय नहीं ले रही है। इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किसी व्यक्तिगत न्यायाधीश की गरिमा की रक्षा के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि न्याय प्रशासन को बदनाम होने से बचाने के लिए किया जाता है। समुदाय के सामान्य हित में यह आवश्यक है कि न्यायालयों के अधिकार को बाधित नहीं किया जाना चाहिए और न्याय के प्रशासन में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह अदालत और अवमानकर्ता के बीच का मामला है और तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसका प्रयोग न्याय के प्रशासन, कानून की महिमा और अदालतों की गरिमा की सहायता के लिए संक्षिप्त तरीके से किया जाता है। ऐसे किसी भी कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसमें न्याय प्रशासन की निष्पक्षता और निष्पक्षता में जनता के विश्वास को हिलाने की प्रवृत्ति हो।

(जोर दिया गया) 48। किसी व्यक्ति को नागरिक अवमानना का दोषी ठहराने के लिए, "जानबूझकर अवज्ञा" एक अनिवार्य आवश्यकता है। क्या अवमानक का आचरण है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

रिकॉर्ड पर सामग्री और परिचर परिस्थितियों का आकलन करके जानबूझकर और जानबूझकर विचार किया जा सकता है।

निजी मुद्दे

49. हम अपने आप को चार प्रश्नों पर व्यापक रूप से संबोधित करना चाहेंगे: (i) क्या अपने मुवकिल की ओर से अदालत में एक वकील/अधिवक्ता द्वारा दिए गए वचन के रूप में आश्वासन का जानबूझकर उल्लंघन अधिनियम 1971 की धारा 2 (बी) के तहत "दीवानी अवमानना" के रूप में माना जाएगा?

((ii) किसी पक्ष को दिए गए वचन और अदालत को दिए गए वचन के बीच अंतर होता है। अदालत को दिया गया वचन अधिनियम 1971 के प्रावधानों को आकर्षित करता है, जबकि समझौते के समझौते के माध्यम से या अन्यथा किसी पक्ष को दिया गया वचन उक्त अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा। क्या वर्तमान मामले में यह कहा जा सकता है कि अदालत को कोई वचन दिया गया था?

((ग) क्या अवमानना न्यायालय के पास किसी भी अवमाननापूर्ण लेन-देन को अवैध या अमान्य घोषित करने की शक्ति है? दूसरे शब्दों में, हालांकि मुकदमे की संपत्ति का हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य नहीं है, फिर भी जब अदालत अवमानना कार्यवाही में इस तरह के हस्तांतरण पर विचार कर रही है, तो क्या अदालत कानून की महिमा बनाए रखने के लिए ऐसे लेनदेन को अमान्य घोषित कर सकती है?

((iv) क्या अवमाननापूर्ण लेन-देन के हितग्राहियों को अवमानना की कार्यवाही में इस आधार पर सुनवाई का अधिकार है कि वे आवश्यक या उचित पक्षकार हैं क्योंकि वे बिना किसी सूचना के मूल्य के लिए वाद संपत्ति के वास्तविक खरीदार हैं?

(v) क्या अवमानकर्ताओं द्वारा दी गई माफी स्वीकार करने योग्य है या यह जिम्मेदारी से बाहर निकलने के लिए एक कानूनी चाल है?

इरादतन अवज्ञा क्या है?

50. यह तय करने के लिए कि क्या अपीलार्थी दीवानी अवमानना के दोषी हैं, हम न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (बी) का उल्लेख करना चाहेंगे, जो निम्नानुसार है:

— 1099

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1100 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

"2. परिभाषाएँ।— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

×××

×××

×××

(ख) "दीवानी अवमानना" का अर्थ है किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या किसी न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना।

51. द ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठा संस्करण, पृष्ठ 1599 पर, नीचे के रूप में "विलफुल" है:

"इच्छा की सचेत गति से आगे बढ़ना; स्वैच्छिक; जानबूझकर। उस परिणाम की योजना बनाना जो वास्तव में घटित होता है; परिकल्पित; जानबूझकर; उद्देश्यपूर्ण; आकस्मिक या अनैच्छिक नहीं।

पूर्व नियोजित; दुर्भावनापूर्ण; बुरे इरादे से, या किसी बुरे उद्देश्य या उद्देश्य के साथ, या प्राकृतिक परिणामों के लिए अस्पष्टता के साथ किया गया; गैरकानूनी; कानूनी औचित्य के बिना।

एक कार्य या चूक "जानबूझकर" की जाती है, यदि स्वेच्छा से और जानबूझकर और कुछ ऐसा करने के विशिष्ट इरादे से किया जाता है जिसे कानून मना करता है, या कुछ ऐसा करने में विफल रहने के विशिष्ट इरादे से जिसे कानून करने की आवश्यकता है; अर्थात्, बुरे उद्देश्य के साथ या तो कानून की अवज्ञा करना या अवहेलना करना। यह कई अर्थों वाला एक शब्द है, जिसकी बनावट अक्सर इसके संदर्भ से प्रभावित होती है। नागरिक कार्यों में, शब्द (जानबूझकर) अक्सर एक ऐसे कार्य को दर्शाता है जो जानबूझकर, या जानने वाला, या स्वैच्छिक है, जैसा कि आकस्मिक से अलग है। लेकिन जब एक आपराधिक संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है तो इसका आम तौर पर मतलब होता है एक बुरे उद्देश्य के साथ किया गया कार्य; बिना किसी उचित बहाने के; जिद्दी, जिद्दी, विकृत रूप से।

52. नियाज़ मोहम्मद और अन्य मामले में यह अदालत। हरियाणा राज्य

और अन्य ने **(1994) 6 एस. सी. सी. 332** में "जानबूझकर अवज्ञा" अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए कहा था:—

“9. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (बी) (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) का अर्थ है "किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा"। जहाँ अवमानना में किसी पक्ष के पक्ष में दिए गए न्यायालय के आदेश का पालन करने या उसे लागू करने में विफलता शामिल है, यह एक दीवानी अवमानना है। वह व्यक्ति या व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसा आदेश या निर्देश दिया गया है, वह कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत का रुख कर सकता है।

कथित अवमानक के खिलाफ अवमानना के लिए, प्रश्नगत आदेश या निर्देश से देय अधिकार को लागू करने की दृष्टि से। लेकिन ऐसी कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निष्पादन कार्यवाही की तरह नहीं है। जिस पक्ष के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, वह ऐसे आदेश के लाभ का हकदार है। अदालत को इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या कथित अवमानकर्ता को अदालत के निर्देश का पालन और पालन नहीं करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए, किसी विशेष मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। यही कारण है कि अधिनियम के निर्माताओं ने दीवानी अवमानना की अवहेलना करते हुए कहा है कि यह किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा होनी चाहिए। अदालत के निर्देश का पालन न करने के लिए अवमानकर्ता को दंडित करने से पहले, अदालत को न केवल किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश या रिट की अवज्ञा के बारे में संतुष्ट होना चाहिए, बल्कि यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी अवज्ञा जानबूझकर और जानबूझकर की गई थी। दीवानी अदालत निर्णय-ऋणदाता के खिलाफ एक डिक्री को निष्पादित करते समय चिंतित नहीं होती है और इस बात की परवाह नहीं करती है कि क्या किसी भी फैसले या डिक्री की अवज्ञा जानबूझकर की गई थी। एक बार डिक्री पारित हो जाने के बाद यह अदालत का कर्तव्य है कि वह डिक्री को निष्पादित करे जो भी उसका परिणाम हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति की शिकायत की जांच करते समय जिसने अदालत के आदेश की अवज्ञा के लिए अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है, इससे पहले कि ऐसे किसी भी अवमानक को दोषी ठहराया जाए और दंडित किया जाए, अदालत को एक आदेश दर्ज करना होगा कि ऐसी अवज्ञा जानबूझकर और जानबूझकर की गई थी। यदि न्यायालय के संज्ञान में लाए गए किसी विशेष मामले की परिस्थितियों से न्यायालय को संतोष होता है कि यद्यपि अवज्ञा हुई है, लेकिन ऐसी अवज्ञा कुछ मजबूर करने वाली परिस्थितियों का परिणाम है, जिसके तहत अवमानकर्ता के लिए आदेश का पालन करना संभव नहीं था, तो न्यायालय कथित अवमानकर्ता को दंडित नहीं कर सकता है।”

(बल दिया गया)

53. अशोक पेपर में कामगर यूनियन बनाम धरम गोधा और अन्य

(2003) 11 एस. सी. सी. 1 में उल्लिखित, अधिनियम की धारा 2 (बी) के संदर्भ में 'जानबूझकर अवज्ञा' अभिव्यक्ति का अर्थ स्वेच्छा से और जानबूझकर कुछ करने के इरादे से किया गया कार्य या चूक है, जिसे कानून मना करता है या कुछ ऐसा करने में विफल रहने के इरादे से जिसे कानून द्वारा करने की आवश्यकता है। इच्छा का अर्थ जानबूझकर की गई कार्रवाई 1101 है।

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1102 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

बुरे इरादे और बुरे इरादे और उद्देश्य के साथ किया गया। यह एक ऐसा अधिनियम नहीं होना चाहिए, जिसके अनुपालन के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी भी कार्य या चूक की पूर्ण या आंशिक रूप से आवश्यकता होती है और उस पर निर्भर होता है।

54. राम किशन बनाम तरुण बजाज और अन्य (2014) 16 में रिपोर्ट किए गए

एस. सी. सी. 204, यह निम्नानुसार देखा गया:—

“12. इस प्रकार, एक अवमानक को दंडित करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि आदेश की अवज्ञा "जानबूझकर" है। "विलफुल" शब्द एक मानसिक तत्व का परिचय देता है और इसलिए, किसी व्यक्ति के मन में उसके कार्यों का आकलन करने की आवश्यकता होती है, जो किसी के मन की स्थिति का संकेत है। "विलफुल" का अर्थ है जानबूझकर जानबूझकर, सचेत, सोच-समझकर और जानबूझकर इसके परिणामों की पूरी जानकारी के साथ। इसमें आकस्मिक, आकस्मिक, प्रामाणिक या अनजाने में किए गए कार्य या वास्तविक अक्षमता शामिल नहीं हैं। जानबूझकर किए गए कार्यों में अनैच्छिक या लापरवाही से किए गए कार्य शामिल नहीं हैं। इस कार्य को "बुरे उद्देश्य के साथ या बिना किसी उचित बहाने के या जिद्दी, जिद्दी या विकृत तरीके से" किया जाना चाहिए। जानबूझकर किए गए कार्य को लापरवाही, विचारहीन, लापरवाही या अनजाने में किए गए कार्य से अलग किया जाना चाहिए। इसमें लापरवाही या अनैच्छिक रूप से किया गया कोई भी कार्य शामिल नहीं है। एक व्यक्ति के जानबूझकर आचरण का मतलब है कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है और ऐसा करने का इरादा रखता है। इसलिए, उसकी ओर से बुरे उद्देश्य के साथ एक सुनियोजित कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही किसी आदेश की अवज्ञा हो, लेकिन ऐसी अवज्ञा कुछ मजबूर करने वाली परिस्थितियों का परिणाम है जिसके तहत अवमानकर्ता के लिए आदेश का पालन करना संभव नहीं था, अवमानकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता है। "जब तक अवमानना में कुछ हद तक चूक या कदाचार शामिल नहीं है, तब तक समर्पण या ज़ब्त करने का आदेश नहीं दिया जाएगा।" (एस. सुंदरम पिन्नई बनाम वी. आर. पट्टाबिरमन [एस. सुंदरम पिन्नई बनाम वी. आर. पट्टाबिरमन, (1985) 1 एस. सी. सी. 591], राकापल्ली राजा राम गोपाल राव बनाम नरगनी गोविंद सेहराव [राकापल्ली राजा राम गोपाल राव बनाम नरगनी गोविंद सेहराव, (1989) 4 एस. सी. सी. 255:ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 2185], नियाज़ मोहम्मद बनाम हरियाणा राज्य [नियाज़ मोहम्मद बनाम हरियाणा राज्य, (1994) 6 एस. सी. सी. 332:ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 308], चोरडिया ऑटोमोबाइल बनाम एस. मूसा [चोरडिया ऑटोमोबाइल बनाम एस. मूसा, (2000) 3 एस. सी. सी. 282], अशोक पेपर कामगार यूनियन बनाम धरम गोधा [अशोक पेपर कामगार यूनियन बनाम धरम गोधा, (2003) 11 एस. सी. सी. 1], उड़ीसा राज्य बनाम मोहम्मद इलियास [उड़ीसा राज्य बनाम।

मोहम्मद इलियास (2006) 1 एस. सी. सी. 275:2006 एससीसी (एल एंड एस) 122:ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 258] और यूनीवर्थ टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. [यूनीवर्थ टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. (2013) 9 एस. सी. सी. 753]।)।”

(जोर दिया गया) 55। उपरोक्त निर्णय भी इस प्रकार है:—

“11. कानून अदालतों को प्रदत्त अवमानना क्षेत्राधिकार किसी व्यक्ति को उसकी जानबूझकर अवज्ञा/अपमानजनक आचरण या कानून की महिमा में बाधा डालने के लिए दंडित करने की शक्ति देता है, क्योंकि अदालतों द्वारा आदेशित सम्मान और अधिकार एक आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी गारंटी है कि उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और यदि न्यायपालिका के सम्मान को कम किया जाता है तो समाज का पूरा लोकतांत्रिक ताना-बाना ध्वस्त हो जाएगा। निस्संदेह, अवमानना क्षेत्राधिकार कानून की अदालतों के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन यह अपने आप में सावधानी की एक कड़ी के रूप में काम करता है और जब तक, इस प्रकार, अन्यथा उचित संदेह से परे संतुष्ट नहीं होता है, तब तक कानून अदालतों के लिए अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना न तो उचित होगा और न ही उचित होगा। कार्यवाही प्रकृति में अर्ध-आपराधिक है, और इसलिए, इन कार्यवाही में आवश्यक सबूत का मानक सभी उचित संदेह से परे है। बल्कि केवल संभावनाओं पर अवमानना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अधिकारियों पर अवमानना के लिए सजा देना खतरनाक होगा। (वी. जी.

निगम बनाम केदार नाथ गुप्ता [वीजी निगम बनाम केदार नाथ गुप्ता, (1992)

4 एससीसी 697:1993 एससीसी (एल एंड एस) 202:(1993) 23 एटीसी 400], छोटू राम बनाम उर्वशी गुलाटी [छोटू राम बनाम उर्वशी गुलाटी, (2001) 7 एससीसी 530:2001 एससीसी (एल एंड एस) 1196], अनिल रतन सरकार बनाम हीरक घोष [अनिल रतन सरकार बनाम हीरक घोष, (2002) 4 एससीसी 21], बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम सद्गुद्दीन हसन दया [बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम सद्गुद्दीन हसन दया, (2004) 1 एससीसी 360], सहदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। [सहदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 3 एस. सी. सी. 705:(2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 451] और नेशनल

फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम टुनके अलंकस [नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम टुनके अलंकस (2013) 9 एस. सी. सी. 600:(2013) 4 एस. सी. सी. (सी. वी.) 481:(2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 172]]”

(जोर दिया गया) 56। इसलिए, अभिव्यक्ति या शब्द "विलफुल" का अर्थ है ऐसा कार्य या चूक जो स्वेच्छा से या जानबूझकर और 1103 के विशिष्ट इरादे के साथ किया जाता है।

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1104

कुछ ऐसा करना जिसे कानून मना करता है या विशिष्ट इरादे से कुछ ऐसा करने में विफल रहने के लिए जिसे कानून द्वारा करने की आवश्यकता है, अर्थात् बुरे उद्देश्य से या तो कानून की अवज्ञा करना या उसकी अवहेलना करना। इसका अर्थ है जानबूझकर बुरे इरादे से या बुरे इरादे या उद्देश्य से किया गया कार्य।

टर्म "अंडरटेक"

57..... ब्लैक लॉ डिक्शनरी, पाँचवाँ संस्करण निम्नलिखित शब्दों में "उपक्रम" की व्याख्या करता है:

“एक वादा, सगाई या शर्त। एक पक्ष द्वारा दूसरे के साथ एक अनुबंध के लिए एक जुड़ाव, जैसा कि एक दूसरे के लिए पक्षों के आपसी जुड़ाव से अलग है। यह आवश्यक रूप से एक विचार का संकेत नहीं देता है। कुछ विशेष अर्थों में, एक पक्ष या उसके वकील द्वारा कानूनी कार्यवाही के दौरान दिया गया एक वादा, आम तौर पर अदालत या विरोधी पक्ष से कुछ रियायत प्राप्त करने की शर्त के रूप में। किसी भी रूप में एक वादा या सुरक्षा।”

58..... एम. वी. मेंगूह कार्यालय सीई और एक अन्य ने (1992) क्यू. बी. 270 में रिपोर्ट किया: (1992) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 73:(1992) 4 सभी ई. आर. 97, अभिव्यक्ति "उपक्रम" से निम्नलिखित तरीके से निपटा गया है:

“यदि कोई पक्षकार, या उसकी ओर से वकील या वकील, अदालत को इस विश्वास से अवगत कराने के लिए कार्य करता है कि एक वचन दिया जा रहा है, तो वह पक्ष बाध्य होगा और यह कोई जवाब नहीं होगा कि उसने यह नहीं सोचा था कि वह दे रहा था या उसे गलत समझा गया था।”

(जोर दिया गया) 59। चूंकि पूरा विवाद इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या उच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान वकील द्वारा दिया गया बयान उनके मुक्किलों की ओर से एक वचन था और यदि हां तो क्या ऐसा वचन अदालत को दिया गया था, हमें इस मुद्दे पर दो निर्णयों पर गौर करना चाहिए; एक बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा और दूसरा कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। द बॉम्बे हाई

बजरंगलाल गंगाधर खेमका और एक अन्य बनाम कपूरचंद में न्यायालय

ए. आई. आर. 1950 बॉम 336 में रिपोर्ट की गई लिमिटेड ने एक ऐसी प्रथा पर ध्यान दिया जिसमें वचन पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया था कि यह अदालत को दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि अभिव्यक्ति "उपक्रम" लंबे अभ्यास के माध्यम से प्राप्त करने के लिए आया था, एक तकनीकी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

अर्थ। उच्च न्यायालय ने एम. सी. चगला, सी. जे. के माध्यम से बोलते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

“....खंड में यह नहीं कहा गया है कि वचन किसे दिया गया है, और यह हो सकता है कि यह अभिनिर्धारित करना संभव होगा कि चूंकि पक्षकार अपने बीच विवाद का निपटारा कर रहे थे, इसलिए वचन एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया था; या, सबसे अधिक, केवल एक चीज जिसका आग्रह किया जा सकता है वह यह होगी कि अभिव्यक्ति अस्पष्ट है, और अवमानना के मामले में, जब तक कि न्यायालय को स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं किया जाता है कि वचन न्यायालय को दिया गया था, तब तक न्यायालय चूक करने वाले व्यक्ति को जेल में डालने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन, हमारी राय में, "उपक्रम" अभिव्यक्ति लंबे अभ्यास के

(जोर दिया गया) 60। इसके विपरीत दृष्टिकोण कलकत्ता हाई के हैरिस, सी. जे. द्वारा लिया गया था।

पूर्ववर्ती मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय द्वारा पारित एक समझौता डिग्री जिसमें एक वचन पत्र होता है, न्यायालय की अतिरिक्त मंजूरी के साथ पक्षों के एक समझौते से अधिक कुछ नहीं था। न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अर्थ एक समझौते से अधिक कुछ नहीं हो सकता है और इसकी समझौते से बड़ी कोई पवित्रता नहीं थी। इसके विपरीत, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बजरंगलाल गंगाधर खेमका (उपरोक्त) मामले में निष्पादन कार्यवाही और अवमानना की कार्यवाही के बीच अंतर किया था जो एक वचन के जानबूझकर चूक से उत्पन्न होती है। निर्णय में उस लंबे समय से चली आ रही प्रथा का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार "उपक्रम" अभिव्यक्ति तकनीकी और कानूनी अर्थ और समझ हासिल करने के लिए आई थी। यह देखा गया कि "जब कोई पक्ष उपक्रम करता है" अभिव्यक्ति का उपयोग न्यायालय को एक वचन देने के लिए किया जाता है जो उस समय से अलग होता है जब एक वकील कहता है कि वह अपने मुवकिल की ओर से उपक्रम करता है। जब कोई व्यक्ति न्यायालय को वचन देता है, तो यह दूसरे पक्ष को नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय को दिया जाता है, और यह कहा जाना पवित्रता रखता है। इसलिए, जब कोई न्यायालय सहमति की शर्तों में एक वचन को मूर्त रूप देने के बाद एक डिग्री पारित करता है, तो यह पता

चलता है कि न्यायालय ने विशेष पाठ्यक्रम को मंजूरी दी थी और सहमति की शर्तों पर अपना प्रभाव डाल दिया था। यह न्यायालय निशा कांतो राय (ऊपर) में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार की तुलना में बजरंगलाल गंगाधर खेमका (ऊपर) में व्यक्त किए गए विचार से सहमत था। इसके बाद सान्याल समिति को निर्देश दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

रिपोर्ट, जो अधिनियम **1971** के अधिनियमन से पहले तैयार की गई थी और उसके बाद अधिनियम **1971** की धारा **2 (बी)** की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने राम नारंग (उपरोक्त) मामले में कहा था:—

“18. अधिनियम का विधिवत विस्तार किया गया है। यह अन्य बातों के साथ-साथ शर्तों की अवहेलना के लिए प्रावधान करता है और अवमानना में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए बेहतर आधार निर्धारित करता है। अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (बी) नागरिक अवमानना की अवहेलना करती है जिसका अर्थ है "किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन"। ((1) न्यायालय की प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा, और (2) न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन, इन दो श्रेणियों के मामलों का विश्लेषण किया गया है। जहाँ तक प्रथम श्रेणी का संबंध है, "कोई भी" शब्द आगे शक्ति की व्यापक प्रकृति को इंगित करता है। निर्णय के बाद पारित आदेश और सहमति से पारित आदेश के बीच कोई अंतर वैधानिक रूप से नहीं किया जाता है। यह पहली श्रेणी दूसरी से अलग है और इसे दूसरी श्रेणी का हिस्सा बनाने या रंग लेने के रूप में नहीं माना जा सकता है। विधायी उद्देश्य स्पष्ट रूप से दोनों के बीच अंतर करना और दूषित व्यवहार के अलग-अलग वर्गों का निर्माण करना था। दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड की अदालतों ने माना है कि समझौते को निष्पादित करने से इनकार करके विशिष्ट प्रदर्शन की सहमति डिक्री का उल्लंघन अवमानना की कार्यवाही के माध्यम से दंडनीय है (सी. एच. जाइल्स एंड कंपनी देखें। लिमिटेड वी. मॉरिस [(1972) 1 ऑल ई. आर. 960: [1972] 1 डब्ल्यूएलआर 307 (सीएचडी)])।”

(जोर दिया गया) 62। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 2 (बी), जो नागरिक अवमानना की अवहेलना करती है, में दो अलग-अलग भाग और श्रेणियाँ शामिल हैं, अर्थात्, (i) किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या (ii) किसी अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन। प्रथम श्रेणी के संदर्भ में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कोई भी" न्यायालय को दी गई शक्ति की व्यापक प्रकृति को इंगित करती है और यह कि कानून निर्णय के बाद पारित आदेश या सहमति से पारित आदेश के बीच अंतर नहीं दिखाता है। पहला भाग या श्रेणी अलग है और इसे एक भाग के रूप में या दूसरी श्रेणी से रंग लेने के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस न्यायालय ने सचेत रूप से कहा कि इंग्लैंड में न्यायालयों ने माना है कि एक समझौते को निष्पादित करने से इनकार करके प्रदर्शन की सहमति डिक्री का उल्लंघन दंडनीय था 1107

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1108 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

अवमानना कार्यवाही के माध्यम से। दूसरे भाग के संदर्भ में, राम नारंग (उपरोक्त) में यह देखा गया था कि एक वचन देना समझौता दर्ज करने वाले सहमति आदेश से अलग है। समझौते के उल्लंघन के बाद के मामले में, अवमानना का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन पक्षकार अदालत से निष्पादन या निषेधाज्ञा द्वारा समझौते के आदेश को लागू कर सकता है। हालांकि, पूर्व मामले में, जब जानबूझकर अवज्ञा होती है, तो अवमानना आवेदन और कार्यवाही बनाए रखने योग्य होगी। [देखिए: सुमन चड्ढा

और एक अन्य बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 में एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल में रिपोर्ट किया

11536] 63. जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुमन चड्ढा (उपरोक्त) मामले में अभिनिर्धारित किया है, उचित संदेह के मामले में न्यायालयों के लिए अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित और उचित नहीं है क्योंकि कार्यवाहियाँ अर्ध-आपराधिक प्रकृति की हैं और इन कार्यवाहियों में आवश्यक सबूत का मानक सभी उचित संदेह से परे है न कि केवल संभावनाओं से। इस प्रकार, ऐसे मामलों में जहाँ किसी आदेश की दो व्याख्याएँ संभव हैं और यदि कार्यवाही आपत्तिजनक नहीं है, तो अवमानना कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं है और इस उद्देश्य के लिए आदेश को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि

अवमानना कार्यवाही में "सबूत के मानक" और "सबूत के तरीके" के बीच एक अंतर है। अवमानना कार्यवाही इस अर्थ में स्वतः सामान्य है कि साक्ष्य का सख्त कानून और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, अवमानना कार्यवाही में अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होनी चाहिए।

64. ऊपर उल्लिखित सुमन चड्ढा (उपरोक्त) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय का निर्णय सुमन चड्ढा बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ए. आई. आर. 2021 एस. सी. 3709 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने क्रमशः पैरा 25 और 26 में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं। पैरा 25 और 26 इस प्रकार हैं:

“25. यह सच है कि किसी पक्ष द्वारा दिए गए वचन को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें इसे बनाया गया था और (i) उपक्रम पक्ष को उपार्जित लाभ; और (ii) विरोधी पक्ष द्वारा किए गए नुकसान/क्षति। यह भी सच है कि आम तौर पर इस सवाल को कि क्या कोई पक्ष अवमानना का दोषी है, अवज्ञा और उसकी जानबूझकर प्रकृति के विशिष्ट संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि उसके बाद के आचरण के आधार पर। जबकि यह देखने के लिए अदालत के लिए खुला है कि क्या कथित अवमानक का बाद का आचरण पहले से की गई अवमानना को बढ़ाने के समान होगा,

अवमानना के कार्य का निर्धारण केवल बाद के आचरण पर आधारित नहीं हो सकता है।

26. लेकिन पक्ष का बाद का आचरण एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाल सकता है कि क्या यह केवल प्रतिबद्धता का सम्मान करने में पक्ष की अक्षमता थी या यह अदालत को धोखा देने के लिए एक बड़ी साजिश का हिस्सा था।”

65. रीटा मार्कडेय बनाम सुरजीत सिंह अरोड़ा ने (1996) 6 में रिपोर्ट किया

एस. सी. सी. 14, यह देखा गया कि भले ही पक्षों ने अदालत के समक्ष एक वचन का नेतृत्व नहीं किया हो, लेकिन अगर अदालत को किसी पक्ष द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर किसी विशेष कार्रवाई या निष्क्रियता को मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया गया था और अदालत अंततः यह मानती है कि पक्ष ने कभी भी उक्त अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया था या ऐसा अभ्यावेदन गलत था, तो पक्ष अवमानना करने का दोषी होगा। यह देखा गया:—

“12. कानून अच्छी तरह से तय है कि यदि कोई पक्ष अदालत को उस परिसर को खाली करने का वचन देता है जिससे वह अदालत के आदेशों के तहत बेदखल होने के लिए उत्तरदायी है और इसका स्पष्ट और जानबूझकर उल्लंघन होता है तो यह दीवानी अवमानना के बराबर है, लेकिन चूंकि, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने इस अदालत के आदेश में परिकल्पित किसी भी वचन को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए उसके उल्लंघन के लिए दंडित किए जाने का सवाल ही नहीं उठता है। हालाँकि, हमारे सुविचारित विचार में ऐसे मामले में भी जहां ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया है, मुकदमे के लिए एक पक्ष को ऐसी अवमानना के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि अदालत को ऐसे पक्ष के प्रतिनिधित्व के आधार पर किसी विशेष कार्रवाई या निष्क्रियता को मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया जाता है और अदालत अंततः यह मानती है कि पक्ष ने कभी भी ऐसे प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया था या ऐसा प्रतिनिधित्व गलत था। दूसरे शब्दों में, यदि यहां प्रत्यर्थी के अभ्यावेदन पर न्यायालय को वाद परिसर की छुट्टी के लिए समय बढ़ाने का आदेश पारित करने के लिए राजी किया गया था, तो उसे न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है, इसके बावजूद कि वचन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यावेदन गलत था और प्रत्यर्थी ने कभी भी उस पर कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया था।...”

(जोर दिया गया) 66। इस प्रकार, भले ही हम यह मान लें कि विद्वान वकील ने अपने मुवक्किलों के निर्देश पर अदालत को कोई "वचन" नहीं दिया था, 1109

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1110

रीटा मार्कडेय (ऊपर) में की गई टिप्पणियाँ, महत्वपूर्ण नहीं हैं और एक अन्य पहलू का उल्लेख करती हैं जब अवमानना क्षेत्राधिकार को लागू किया जा सकता है, जो उन मामलों से अलग और अलग है जहां पक्षों ने अदालत को वचन दिया है और उसके बाद जानबूझकर इसका पालन करने और पालन करने से इनकार कर दिया है। 67. 1982 (1) आर. सी. आर. 323 (13) में दर्ज गोविंद कौर बनाम हरदेव मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष एक सवाल उठा कि क्या किरायेदार अदालत की अवमानना का दोषी था। 13 मार्च, 1980 को जब फैसला सुनाया गया तो किरायेदार के वकील ने

अदालत से दुकान संख्या 6 को खाली करने के लिए समय देने का अनुरोध किया। उन्हें दो महीने का समय दिया गया था। उसने दुकान संख्या 6 के खाली कब्जे को उस दिन से दो महीने की समाप्ति पर या उससे पहले मकान मालिक को देने का बीड़ा उठाया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि: —

“...इसे दुकान संख्या 6 को खाली करने के लिए पक्षों के बीच समझौते के माध्यम से एक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। यह न्यायालय के लिए एक वचन है। वचन एक वचन है, जो किसी कार्यवाही के लिए एक पक्ष द्वारा न्यायालय को विशेष कार्य करने या न करने के लिए दिया जाता है, जो एक निषेधाज्ञा के रूप में लागू करने योग्य है क्योंकि जब न्यायालय किसी पक्ष द्वारा दिए गए वचन को स्वीकार करता है, तो उसका आदेश सार में एक निषेधाज्ञा के बराबर होता है। किसी व्यक्ति या निगम द्वारा न्यायालय को लंबित कार्यवाहियों में दिया गया वचन जिसके आधार पर न्यायालय किसी विशेष कार्यवाई या निष्क्रियता को मंजूरी देता है, न्यायालय द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के समान बल रखता है और वचन का उल्लंघन अवमानना के बराबर कदाचार है। 'न्यायालय को दिए गए वचन' को सहमति आदेश से अलग किया जाना चाहिए, या जिसे दीवानी कार्यवाही में पक्षों के नेतृत्व में समझौता याचिका पर पारित आदेश के रूप में जाना जाता है। एक सहमति आदेश केवल पक्षों के बीच एक समझौता है, भले ही न्यायालय इसे रिकॉर्ड कर सकता है और अपने आदेश को उसमें जोड़ सकता है और किसी सहमति आदेश की शर्तों का पालन करने में किसी पक्ष की विफलता के मामले में, घायल पक्ष अवहेलना के लिए चूककर्ता को करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है; उसका उपाय विशिष्ट प्रदर्शन या निषेधाज्ञा के माध्यम से है। हालांकि, जब कोई पक्ष न्यायालय को यह वचन देने पर अदालत से आदेश प्राप्त करता है कि वह एक विशेष कार्यवाई या निष्क्रियता का मार्ग अपनाएगा, तो ऐसा वचन स्वयं न्यायालय द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के रूप में कार्य करता है क्योंकि न्यायालय ने उपक्रम के विश्वास पर अपना आदेश दिया है, उदाहरण के लिए, डिक्री या आदेश के निष्पादन पर रोक।”

(बल दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

68. अदालत ने तब व्यक्त किया कि वे इस राय की अवहेलना कर रहे थे कि यह अदालत के लिए एक बिना शर्त और अयोग्य वचन था, भले ही उस प्रभाव के शब्दों का उपयोग अदालत के बयान या आदेश में नहीं किया गया था।

69. इस प्रकार, पक्षकार या उनके वकील के बयानों में या न्यायालय के आदेशों और फरमानों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा सुझाव नहीं देता है, "एक पक्षकार" वचन देता है "या" एक गंभीर वचन देता है "या" यह पक्षकारों के निर्देशों पर बार में कहा गया है कि संपत्ति नहीं बेची जाएगी ", का अर्थ है अदालत के लिए एक निहित वचन। उपक्रम को हमेशा न्यायालय के लिए एक उपक्रम के रूप में समझा जाता है, जिसे समर्पण कार्यवाही द्वारा लागू किया जा सकता है।

70. हम 2013 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 16266 में 2015 के सिविल आवेदन संख्या 11412 में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर वापस जाते हैं, जिसमें विद्वान वकील द्वारा अपने मुवक्किलों के निर्देशों पर दिए गए आश्वासन/वचन को दर्ज किया गया है कि विवादित प्रविष्टि की विषय वस्तु के संबंध में संपत्ति को मुख्य याचिका के निपटारे तक नहीं बेचा जाएगा। आदेश इस प्रकार है:

“श्री संजनवाला द्वारा बार में अपने मुवक्किलों के निर्देश पर कहा गया है कि इस प्रविष्टि और याचिका की विषय वस्तु वाली संपत्ति को तब तक नहीं बेचा जाएगा जब तक कि मुख्य याचिका की सुनवाई और निर्णय नहीं हो जाता है, जो श्री मिहिर ठाकुर की चेतना को संतुष्ट करता है जो विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाव मेहता के साथ उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि वह निर्देशों पर लेटर्स पेटेंट अपील को दबा नहीं सकते हैं। इसलिए, इस सिविल आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है। यह बिना कहे चला जाता है कि आदेश विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से पारित किया गया था।”

(जोर दिया गया) 71। कानून के सिद्धांतों को वनहीन मानते हुए, इस न्यायालय के लिए यह कहना बहुत अधिक होगा कि उच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिया गया बयान केवल एक पक्ष को दिया गया आश्वासन था और यह अदालत को दिया गया वचन नहीं था ताकि "नागरिक अवमानना" के परिणाम सामने आ सकें।

72. यह सच है कि किसी मुकदमे में एक पक्ष द्वारा दिया गया प्रत्येक वचन न्यायालय के लिए एक वचन नहीं हो सकता है; 1111 के बीच एक अंतर है।

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1112

दूसरे पक्ष को दिया गया वचन और न्यायालय को दिया गया वचन। दूसरे पक्ष को दिए गए वचन का उल्लंघन अदालत की अवमानना नहीं हो सकता है। हालाँकि, क्या कोई विशेष उपक्रम न्यायालय या विरोधी पक्ष के लिए एक वचन है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और उपयोग की गई भाषा पर निर्भर करना चाहिए। उधर के मामले में, यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि उन्होंने अदालत के बाहर दूसरे पक्ष के साथ एक समझौते पर बातचीत की थी और उच्च न्यायालय को इसकी सूचना दी थी और उच्च न्यायालय ने मुवक्किलों के निर्देश पर विद्वान वकील द्वारा दिए गए वचन को शामिल करते हुए आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े। भले ही पक्षों ने अदालत के बाहर एक समझौते पर बातचीत की हो और अदालत को इसकी सूचना दी हो और अदालत ने एक आदेश पारित किया हो, इस तरह की समझ के संदर्भ में, यह वारंट करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी कि अदालत को वचन नहीं दिया गया था।

73. एक वकील द्वारा दिया गया एक वचन या आश्वासन जिसके आधार पर अदालत एक विशेष कार्रवाई का फैसला करती है, अधिनियम 1971 की धारा 2 (बी) के तहत निर्धारित "वचन" के दायरे में आती है और जिसका उल्लंघन "दीवानी अवमानना" का गठन करेगा। जैसा कि एम. वी. में किया गया है। इस न्यायालय ने राम नारंग (उपरोक्त) मामले में यह भरोसा व्यक्त किया कि यदि उनकी ओर से कोई पक्ष या वकील या वकील, ताकि अदालत को यह विश्वास दिलाया जा सके कि कोई वचन दिया जा रहा है, तो वह पक्ष बाध्य होगा और यह कोई जवाब नहीं होगा कि उसने यह नहीं सोचा था कि वह यह दे रहा था या उसे गलत समझा गया था। किसी व्यक्ति द्वारा किसी लंबित कार्यवाही में अदालत को दिए गए वचन का उल्लंघन, जिसके विश्वास पर अदालत किसी विशेष कार्रवाई को मंजूरी देती है, अवमानना के बराबर कदाचार है।

74. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय को यह कहते हुए न्यायसंगत ठहराया गया था कि अपीलकर्ताओं को दीवानी अवमानना का दोषी ठहराते हुए, लेकिन इस वचन के लिए, 2013 के विशेष दीवानी आवेदन संख्या 16266 में प्रतिवादी जो 2015 के एल. पी. ए. (स्टाम्प) No.1196 में अपीलकर्ता थे (इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी) ने अपील को वापस नहीं लिया होता क्योंकि उस पर दबाव नहीं डाला गया था।

75. उच्च न्यायालय का यह कहना सही है कि यह आई. डी. 1 पर अदालत को दिया गया यह वचन है जिसने प्रतिवादियों को उक्त अपील को वापस लेने के लिए राजी किया और यह अदालत को दिया गया ऐसा गंभीर आश्वासन है जिसने उन्हें अवमानकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए बयान को दर्ज करके अपील को वापस लेने के लिए मजबूर किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

76. इस प्रकार, अपने मुवक्किल की ओर से अदालत में एक वकील/अधिवक्ता द्वारा दिए गए वचन के रूप में आश्वासन का जानबूझकर उल्लंघन अधिनियम 1971 की धारा 2 (बी) के तहत "दीवानी अवमानना" के रूप में माना जाएगा।

77. अभिलेख पर सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारा यह भी विचार है कि मामले में जो वचन दिया गया है वह अदालत को दिया गया था।

78. हमारे द्वारा तैयार किए गए पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर उसी के अनुसार दिया जाता है।

क्या परस्पर लेन-देन की आवाज़ आती है?

79. अब हम किसी भी अवमाननापूर्ण लेन-देन को अवैध या अमान्य घोषित करने की अवमानना अदालत की शक्ति के संबंध में हमारे द्वारा तैयार किए गए तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ते हैं।

80. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

भारत और अन्य बनाम डॉ. विजय माल्या ने 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी में रिपोर्ट किया

826, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अवमानकर्ता को उसके अपमानजनक आचरण के लिए दंडित करने के अलावा, कानून की महानता यह मांग कर सकती है कि न्यायालय द्वारा उचित निर्देश जारी किए जाएं ताकि इस तरह के आपत्तिजनक आचरण के परिणामस्वरूप प्राप्त कोई भी लाभ पूरी तरह से अमान्य हो जाए। इस दृष्टिकोण के लिए न्यायालय को या तो कथित लेन-देन को अमान्य घोषित करके या संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश पारित करके विचाराधीन लेन-देन को उलटने के लिए निर्देश जारी करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि यह देखा जा सके कि अवमानकर्ता की ओर से अनुचित आचरण अवमानकर्ता या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए जारी न रहे।

81. इस संदर्भ में, के निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा

क्लार्क और अन्य में चांसरी डिवीजन। चैंडबर्न और अन्य ने बताया

(1985) 1 समस्त ई. आर. 211 में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी निषेधाज्ञा या न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा में किया गया कार्य न केवल न्यायालय की अवमानना है, बल्कि एक अवैध और अमान्य कार्य भी है जो इसलिए दूसरों के अधिकारों और देनदारियों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था

इस न्यायालय ने सत्यव्रत विश्वास और अन्य बनाम कल्याण कुमार किस्कु और

अन्य ने (1994) 2 एस. सी. सी. 266 में रिपोर्ट किया, जिसमें प्रत्यर्थियों द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ अवमानना अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया गया था, और अवमानना कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि एक उप किरायेदारी बनाई गई थी जबकि स्थिति 1113 थी।

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1114 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

क्वो ऑर्डर चालू था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उप-किरायेदारी का निर्माण यथास्थिति आदेश का उल्लंघन था और पक्षों को यथास्थिति आदेश की तारीख पर मौजूद स्थिति में हटा दिया गया था। इस न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ, इस प्रकार टिप्पणी की:

“23. ... इस तरह के आदेश को दंड से मुक्त पक्षों द्वारा दरकिनार नहीं किया जा सकता है और अदालत से अपना आशीर्वाद देने की उम्मीद की जा सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवमानना की कार्यवाही में सोमानी बिल्डर्स पक्षकार नहीं थी। यह उन पक्षों के अधिकारों के हनन में लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, जो मूल रूप से मुकदमा कर रहे थे। यदि उप-किरायेदारी के अधिकार को मान्यता दी जाती है, तो 15.9.1988 की यथास्थिति कैसे बनी रहती है? इसलिए, सबलीज का अनुदान यथास्थिति के क्रम के विपरीत है। यथास्थिति के क्रम में किया गया कोई भी कार्य स्पष्ट रूप से अवैध है। उप-पट्टा देने सहित सभी कार्य स्पष्ट रूप से अवैध हैं।”

(जोर दिया गया) 82। हम इस न्यायालय के दो फैसलों से अवगत हैं—एक मामले में

थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड बनाम नानक बिल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स प्राइवेट

लिमिटेड और अन्य ने (2013) 5 एस. सी. सी. 397 और टी. रवि (ऊपर) में रिपोर्ट किया। इन दोनों निर्णयों में, यह विचार लिया गया है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (संक्षेप में, “अधिनियम 1882”) की धारा 52 मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किए गए हस्तांतरण को अमान्य नहीं करती है, बल्कि केवल ऐसे हस्तांतरण को उन अधिकारों के अधीन करती है जो अंततः अदालत द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। 83. थॉमसन प्रेस (उपरोक्त) में, जे. टी. एस. ठाकुर, ने अपने अलग फैसले में एम. वाई. इकबाल, जे. द्वारा लिखित फैसले के पूरक के रूप में निम्नलिखित टिप्पणी की:

“53. इसलिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मुकदमे की संपत्ति का हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य नहीं है और ऐसी किसी भी संपत्ति का खरीदार लंबित मुकदमे में वादी के अधिकारों के अधीन सौदा करता है। यद्यपि उपरोक्त निर्णय एक तथ्य स्थिति से संबंधित नहीं हैं जहां बिक्री विलेख को एक सक्षम अदालत द्वारा जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन में निष्पादित किया जाता है, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि इस तरह के किसी भी निषेधाज्ञा के उल्लंघन से हस्तांतरण क्यों होना चाहिए, चाहे वह पूर्ण बिक्री के रूप

में हो या अन्यथा अप्रभावी। उल्लंघन करने वाले पक्ष को निस्संदेह उसके द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए दंडित करने का दायित्व वहन करना पड़ सकता है, लेकिन बिक्री अपने आप में

लेन-देन के पक्षों के बीच केवल किसी भी निर्देश के अधीन वैध रह सकता है जो सक्षम अदालत विक्रेता के खिलाफ मुकदमे में जारी कर सकती है।"

(जोर दिया गया) 84। ऊपर निर्दिष्ट थॉमसन प्रेस (उपर्युक्त) पर टी. रवि (उपर्युक्त) में इस प्रस्ताव के लिए भरोसा किया गया है कि अधिनियम 1882 की धारा 52 का प्रभाव किसी पक्ष द्वारा मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किए गए हस्तांतरण को शून्य नहीं बनाता है; हस्तांतरण निश्चित रूप से मुकदमे के परिणाम के अधीन वैध रहता है। विचाराधीन लघु खरीदार अपने विक्रेता के समान कानूनी अधिकारों और दायित्वों का हकदार होगा या उसे पूरा करेगा जैसा कि अंततः न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

85. इस न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड और एक अन्य मामले में (1996) 4 एस. सी. सी. 622 में रिपोर्ट की,

यह अभिनिर्धारित किया गया कि रोक या निषेधाज्ञा के आदेश के उल्लंघन या उल्लंघन में जो कुछ किया गया है, उसके कानूनी परिणामों को पूर्ववत किया जाना चाहिए और पक्षों को उसी स्थिति में वापस रखा जा सकता है जो वे रोक या निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश से तुरंत पहले थे ताकि चूक करने वाले पक्ष को कोई अनुचित लाभ न मिले। इस न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा तय किए गए मामलों पर भरोसा करते हुए कहा:

"अवमानकर्ता को अपनी अवमानना के फल का आनंद लेने या बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

× × ×

× × ×

× × ×

18. उपरोक्त सिद्धांत दीवानी अदालतों द्वारा जारी निषेधाज्ञा के आदेशों के उल्लंघन के मामले में भी लागू किया गया है। क्लार्क बनाम चैडबर्न [(1985) 1 ऑल ई. आर. 211] में सर रॉबर्ट मेगारी वी. सी. ने कहा:

"मुझे इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण का हवाला देने की आवश्यकता नहीं है कि यह उच्च महत्व का है कि अदालत के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना अदालत की अवमानना के रूप में दंडनीय है, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की अवज्ञा को उचित रूप से अवैध बताया जा सकता है। यदि इस तरह की अवज्ञा से आदेशित व्यक्ति यह दावा करते हैं कि उन्होंने दूसरों के अधिकारों और देनदारियों में कुछ आरोप वैध रूप से लगाए हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि यह क्यों कहा जाना चाहिए कि हालांकि वे 1115 के लिए अदालत की अवमानना के लिए दंड के लिए उत्तरदायी हैं।

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1116 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

उन्होंने वही किया जो उन्होंने किया, फिर भी वे कार्य वैध रूप से किए गए थे। बेशक, यदि कोई कार्य किया जाता है, तो इसे केवल यह इंगित करके पूर्ववत नहीं किया जाता है कि यह कानून के उल्लंघन में किया गया था। यदि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए कोई बैठक आयोजित की जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि बैठक आयोजित नहीं की गई है। लेकिन कानून के उल्लंघन में जो किया गया है उसके कानूनी परिणाम स्पष्ट रूप से अवैधता से बहुत अधिक प्रभावित हो सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग प्रतिबंध की अवहेलना करते हैं, उन्हें यह दावा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए कि उनकी अवज्ञा के फल अच्छे हैं, और उन्हें पैदा करने वाली अवैधता से दूषित नहीं हैं।"

19. उसी प्रभाव के लिए मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के निर्णय सेंचुरी फ्लोर मिल्स लिमिटेड बनाम.एस. सुपिया [ए. आई. आर. 1975 मैड 270:(1975) 2 एम. एल. जे. 54] और सुजीत पाल बनाम प्रवीर कुमार सन [ए. आई. आर. 1986 कैल 220:(1986) 90 सीडब्ल्यूएन 342]। सेंचुरी फ्लोर मिल्स लिमिटेड में [ए. आई. आर. 1975 मैड 270:(1975) 2 एम. एल. जे. 54] मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां कोई कार्य स्थगन या निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन करते हुए किया जाता है, यह अदालत का कर्तव्य है, एक नीति के रूप में, गलत अधिकार निर्धारित करना और गलत काम को बनाए रखने की अनुमति नहीं देना। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति न केवल ऐसे मामले में उपलब्ध है, बल्कि यह न्याय के हित में गलत को पूर्ववत करने के लिए इसका प्रयोग करने के लिए बाध्य है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें निषेधाज्ञा के आदेश के विपरीत एक बैठक आयोजित की गई थी। अदालत ने यह मानने से इनकार कर दिया कि बैठक का आयोजन कानूनी है। इसने पक्षों को उसी स्थिति में वापस डाल दिया जो वे अंतरिम आदेश की सेवा से तुरंत पहले खड़े थे। 20. सुजीत पाल में [ए. आई. आर. 1986 कैल 220:(1986) 90 सी. डब्ल्यू. एन. 342] कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने भी यही विचार रखा है। वहाँ, प्रतिवादी ने निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन करते हुए वादी को जबरन बेदखल कर दिया और संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अदालत ने पुलिस की सहायता से वादी को कब्जा बहाल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि कोई भी तकनीकीता न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय करने से नहीं रोक सकती है। इसने अभिनिर्धारित किया कि आदेश 39 के नियम 2-ए के उद्देश्य को केवल तभी पूरा किया जाएगा जब पीड़ित पक्ष को अधिकार की बहाली के लिए ऐसा अनिवार्य निर्देश दिया जाता है। इसने देखा कि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक था।

21. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस हितकारी नियम को इस न्यायालय द्वारा लागू किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो किसी भी प्रक्रियात्मक या

अन्य तकनीकी आपत्तियाँ। अनुच्छेद 129 एक संवैधानिक शक्ति है और जब इसका प्रयोग अनुच्छेद 142 के साथ किया जाता है, तो ऐसी सभी आपत्तियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। न्यायालय को अपने समक्ष पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।"

(बल दिया गया)

86. विदुर इम्पेक्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम तोश अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामले में यह अदालत (2012)

8 एस. सी. सी. 384 ने इसी तरह के तथ्यात्मक परिदृश्य पर निर्णय लेते हुए कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा के तहत किए गए बिक्री लेनदेन का कोई कानूनी आधार नहीं है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"42. ... पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम यह उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं कि प्रत्यर्थी 1 ने प्रत्यर्थी 2 द्वारा निष्पादित 13-9-1988 दिनांकित समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया था। अपीलकर्ता और भगवती डेवलपर्स उस समझौते के लिए पूरी तरह से अजनबी हैं। वे तब सामने आए जब प्रतिवादी 2 ने वाद संपत्ति की बिक्री के लिए अपीलकर्ताओं के साथ एक गुप्त लेनदेन किया और बिक्री के लिए समझौतों को निष्पादित किया, जिसके बाद पंजीकृत बिक्री विलेख किए गए और अपीलकर्ताओं ने भगवती डेवलपर्स के पक्ष में बिक्री के लिए समझौते को निष्पादित किया। ये लेन-देन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था, जिसने प्रतिवादी 2 को मुकदमे की संपत्ति को अलग करने या तीसरे पक्ष का हित पैदा करने से रोक दिया था। इसे अलग तरह से रखने के लिए, अपीलार्थियों के पक्ष में प्रतिवादी 2 द्वारा निष्पादित बिक्री के समझौतों और बिक्री विलेखों की कोई कानूनी पवित्रता नहीं थी। भगवती डेवलपर्स के पक्ष में अपीलार्थियों द्वारा निष्पादित बिक्री समझौते की स्थिति अलग नहीं थी। ये लेन-देन अपीलार्थियों या भगवती डेवलपर्स को कोई अधिकार प्रदान नहीं करते थे। इसलिए, इस प्रश्न के निर्णय के लिए उनकी उपस्थिति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि क्या उत्तरदाता 1 और 2 ने एक बाध्यकारी समझौता किया था और क्या उत्तरदाता 1 उक्त समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की बिक्री का हकदार है।....

(जोर दिया गया) 87। विदुर इम्पेक्स (ऊपर) के फैसले पर इस अदालत ने भरोसा किया था

जेहल तांती और अन्य बनाम नागेश्वर सिंह (मृत) टीएचआर के मामले में।

एल. आर. एस. ने ए. आई. आर. **2013 एस. सी. 2235** में रिपोर्ट किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1118 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

“13. हम अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिसमें कहा गया है:

“23. कौन से विचार और उद्देश्य वैध हैं, और क्या

नहीं।— किसी समझौते पर विचार या उद्देश्य वैध है, जब तक कि -

यह कानून द्वारा निषिद्ध है; या

ऐसी प्रकृति का है कि, यदि अनुमति दी जाती है, तो यह किसी भी कानून के प्रावधानों को विफल कर देगा; या

धोखाधड़ी है; या

इसमें किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुँचाना शामिल है या निहित है; या अदालत इसे अनैतिक मानती है, या सार्वजनिक नीति का विरोध करती है।”

इनमें से प्रत्येक मामले में, किसी समझौते पर विचार या उद्देश्य गैरकानूनी है और ऐसे उद्देश्य या विचार के साथ निष्पादित प्रत्येक समझौता जो गैरकानूनी है, अमान्य है। चूँकि विक्रय विलेख विचारण न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा के आदेश के अनुसार प्रतिवादी 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया था, इसलिए यह गैरकानूनी प्रतीत होता है।

(जोर दिया गया) 88। इस प्रकार, यद्यपि अधिनियम 1882 की धारा 52 एक हस्तांतरण को अमान्य नहीं बनाती है, फिर भी अदालत को अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उक्त लेनदेन को अमान्य घोषित करके या संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश पारित करने के लिए न्यायसंगत ठहराया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवमानकर्ता की ओर से अनुचित आचरण अवमानकर्ता या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए जारी न रहे।

89. उच्च न्यायालय ने अवमानकर्ताओं द्वारा खरीदारों के पक्ष में निष्पादित सभी बिक्री विलेखों को गैर-अचल घोषित कर दिया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि बिक्री विलेख को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए। अवमानकर्ताओं को उस स्थिति को बहाल करने का निर्देश दिया गया था जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के समय प्रचलित थी। हमारी राय में, उच्च न्यायालय को बिक्री विलेखों को अवैध या अमान्य घोषित करने में पूरी तरह से न्यायसंगत ठहराया गया था।

खरीदारों को आवश्यक दलों के रूप में लागू करना

90. अब हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या श्री श्याम दीवान यानी खरीदारों के मुवकिलों को उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना कार्यवाही में पक्षकार उत्तरदाता के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था और क्या उन्हें अंतिम आदेश पारित करने से पहले सुना जाना चाहिए था।

91. सत्यव्रत विश्वास (ऊपर) के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति पक्षों के अधिकारों का अपमान करके लाभ नहीं उठा सकता है। उक्त मामले में एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें पक्षों को विवादित संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, उसमें अपीलार्थी ने अवमानना में कार्य किया और एक सोमानी बिल्डर के पक्ष में एक उप-किरायेदारी बनाई, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था। सोमानी बिल्डर्स ने तर्क दिया कि उन्हें कार्यवाही में एक पक्ष बनाया जाना चाहिए था क्योंकि विवादित संपत्ति में उनका अधिकार था। इस न्यायालय ने उक्त तर्क को खारिज कर दिया और निम्नलिखित टिप्पणी की:

“23. ... प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील श्री चिदंबरम के रूप में यह तर्क देने का कोई फायदा नहीं है कि यथास्थिति आदेश की शर्तों के तहत इस तरह के सबलीज़ पर रोक थी। इसमें संपत्ति की स्थिति के संरक्षण का उल्लंघन करने का प्रभाव है। यह तब और भी अधिक होगा जब यह अदालत की अनुमति के बिना किया जाता है ताकि उस समय की स्थिति को बाधित किया जा सके। यह आदेश का उल्लंघन होगा। मैं किसिम 'एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट' में निहित सिद्धांत का इस मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है जब यथास्थिति आदेश का उल्लंघन करते हुए एक उप-किरायेदारी बनाई गई है। समान रूप से, यह तर्क कि एक अतिक्रमणकारी को भी कानून का सहारा लिए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता है, बेमानी है, क्योंकि 15 सितंबर, 1988

को संपत्ति के संबंध में विवाद की स्थिति से अदालत का संबंध है। इस तरह के आदेश को दंड से मुक्त पक्षों द्वारा दरकिनार नहीं किया जा सकता है और अदालत से अपना आशीर्वाद देने की उम्मीद की जा सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवमानना की कार्यवाही में सोमानी बिल्डर्स पक्षकार नहीं थी। यह उन पक्षों के अधिकारों के अपमान में लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, जो मूल रूप से मुकदमा कर रहे थे। यदि उप-किरायेदारी के अधिकार को मान्यता दी जाती है, तो 15 सितंबर, 1988 तक की यथास्थिति कैसे बनी रहती है? इसलिए, सबलीज का अनुदान यथास्थिति के क्रम के विपरीत है। यथास्थिति के क्रम में किया गया कोई भी कार्य स्पष्ट रूप से अवैध है। सबलीज देने सहित सभी कार्य स्पष्ट रूप से अवैध हैं।

(बल दिया गया)

1119

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1120 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

92. गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उल्लेख करते हुए कहा कि

सत्यव्रत विश्वास (ऊपर) का उल्लेख ऊपर किया गया है: मफतलाल इंडस्ट्रीज

लि. 1994 की ओ. जे. अपील संख्या 16 में 1994 की कंपनी याचिका संख्या 22 में <आई. डी. 1 पर निर्णय लिया गया, जिसे निम्नानुसार देखा गया:

“71. यह कानून के शासन का सार है कि समाज के भीतर हर कोई कानून के शासन द्वारा शासित होता है और उसे खुद को कानून के शासन से बंधा हुआ और उसका पालन करने वाला मानना चाहिए। यह उस राजनीति प्रणाली के लिए मौलिक है जिसे भारत ने अपनाया है और जो संविधान में सन्निहित है कि देश की अदालतों को कानून की व्याख्या करने और उन मामलों के तथ्यों पर इसे लागू करने की शक्तियां निहित हैं जो उनके सामने ठीक से लाए गए हैं। जब एक बार कोई आदेश पारित हो जाता है, जिसे पारित करने का अधिकार न्यायालय के पास होता है, तो उससे बंधे सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे आदेश का पालन करें, जब तक यह बना रहता है, और यह व्यवस्थित प्रशासन और नागरिक सरकार के विध्वंस की ओर प्रवृत्त होगा, यदि पक्ष दंड से मुक्त आदेशों की अवज्ञा कर सकते हैं। यदि अवज्ञा अनियंत्रित हो सकती है, तो इसके परिणामस्वरूप अदालतों के आदेशों का कोई अर्थ नहीं होगा और न्यायिक शक्ति स्वयं एक उपहास बन जाएगी। इस अधिकार पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि अदालत को कानून द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ उचित मामलों में ऐसे शब्दों में निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार है जो अदालत उचित समझती है। उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए मशीनरी प्रदान की गई है जो उस आदेश की अवज्ञा करता है जो कानून के मौलिक नियम के एक हिस्से के रूप में प्रतिबंधित व्यक्ति पर बाध्यकारी है जो समानता को नियंत्रित करता है। आगे जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या आदेश के उल्लंघन में किया गया कार्य स्वयं सुरक्षित है। हमारी राय में, यह विचार रखते हुए कि आदेश की बाध्यकारी परिस्थिति या प्रकृति की परवाह किए बिना सभी परिस्थितियों में इस तरह के लेन-देन से लेन-देन प्रभावित नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन को प्रोत्साहित करना होगा जो जुर्माना लगाने का साहस करता है और इसके परिणामस्वरूप आदेशों की प्रभावी प्रकृति और उस उद्देश्य की प्राप्ति में कटौती होगी जिसके लिए अदालतें मौजूद हैं और न्यायिक शक्ति का प्रयोग करती हैं।

×××

×××

×××

73. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए अवमानना की कार्यवाही को स्वीकार करने के अलावा, शीर्ष अदालत ने निषेधाज्ञा आदेश के विपरीत कब्जे में शामिल उप-किरायेदार को बेदखल करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही को स्वीकार कर लिया है।

निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन में उप-किरायेदारी के निर्माण का परिणाम स्वयं अवैध है जो अधीनता वाले को कब्जे में रहने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। शीर्ष अदालत की यह स्पष्ट घोषणा उस निष्कर्ष पर पहुंचती है जिस पर हम पहुंचे हैं और

कंपनी की दलील है कि किसी भी परिस्थिति में, निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन में किए गए लेनदेन को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।"

(बल दिया गया)

93. सुरजित सिंह और अन्य आदि में।v. हरबंस सिंह और अन्य

ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 135 में प्रतिवेदित, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या एक व्यक्ति जिसे मुकदमा संपत्ति निचली अदालत द्वारा प्रारंभिक डिक्री पारित करने के बाद अलग कर दी गई है, जिसने पक्षों को मुकदमा संपत्ति को अलग करने या अन्यथा स्थानांतरित करने से रोक दिया था, उसे एक पक्ष के रूप में आरोपित करने का अधिकार है। निचली अदालत ने हस्तांतरणकर्ताओं के नेतृत्व में आवेदन को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत के आदेश को निचली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा:

"4. ... प्रतिबंध आदेश की अवहेलना में, अलगाव/असाइनमेंट किया गया था। अगर हम इसे इस तरह से जाने देते हैं, तो यह न्याय और प्रचलित सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों को विफल कर देगा। जब न्यायालय किसी विशेष स्थिति के अस्तित्व का इरादा रखता है, जब वह किसी विशेष स्थिति में होता है, तो उस स्थिति को न केवल बनाए रखने की आवश्यकता होती है, बल्कि यह माना जाता है कि यह तब तक मौजूद है जब तक कि न्यायालय अन्यथा आदेश नहीं देता। इन परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है, साथ ही अधिकार भी है कि वह अलगाव/असाइनमेंट को अपने उद्देश्यों के लिए बिल्कुल नहीं माना जाए। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, प्रीतम सिंह और उनके नियुक्त किए गए लोग, उत्तरदाता, कार्य के आधार पर पक्षकारों के रूप में शामिल होने का दावा नहीं कर सकते हैं। इसलिए, नियुक्त किए गए प्रत्यर्थियों को उसके आदेशों की अवज्ञा करते हुए मुकदमे के पक्षकारों के रूप में निचली अदालत द्वारा शामिल नहीं किया जा सकता था।"

(बल दिया गया)

94. सरविंदर सिंह बनाम दलीप सिंह और अन्य में रिपोर्ट (1996)

5 एस. सी. सी. 539, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या प्रत्यर्थी जिसने अपनी माँ द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलार्थी के नेतृत्व में घोषणा के लिए मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति खरीदी थी, वह पक्षकार के रूप में शामिल होने का हकदार था और कहा:

1121

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1122 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

"5. ... उत्तरदाता निर्विवाद रूप से हीरा देवी द्वारा 26 5-1952 पर निष्पादित और पंजीकृत वसीयत की वैधता या वैधता को चुनौती नहीं दे सकते हैं। हालाँकि यह राजेंद्र कौर के कानूनी उत्तराधिकार के लिए खुला हो सकता है,

जो किसी भी कानूनी रूप से उपलब्ध या मान्य आधारों पर दावे का विरोध करने के लिए पहले के मुकदमे में एक पक्ष था, वे आधार उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थियों को, किसी भी तरह की कल्पना से, मुकदमे के लिए आवश्यक या उचित पक्षकार नहीं कहा जा सकता है। एक आवश्यक पक्ष वह है जिसकी उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक है और जिसकी उपस्थिति के बिना इस मुद्दे पर प्रभावी रूप से और पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया जा सकता है और पक्षों के बीच निर्णय लिया जा सकता है। एक उचित पक्ष वह है जिसकी उपस्थिति विवादों पर प्रभावी और पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए आवश्यक होगी। दोनों ही मामलों में प्रत्यर्थियों को उस मुकदमे के लिए या तो आवश्यक या उचित पक्षकार नहीं कहा जा सकता है जिसमें अपीलार्थी की मां श्रीमती हीरा देवी द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्राथमिक राहत पाई गई थी। इसके अलावा, माना जाता है कि प्रतिवादियों ने पंजीकृत बिक्री विलेखों के अनुसार अधिकार, स्वामित्व और ब्याज का दावा किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजेंद्र कौर के प्रतिवादियों-उत्तराधिकारियों द्वारा 2-12-1991 और 1 2-12-1991 पर निष्पादित किया गया था, मुकदमा लंबित है।

6. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 में परिकल्पना की गई है कि: "भारत की सीमाओं के भीतर अधिकार रखने वाले किसी न्यायालय में किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के लंबित होने के दौरान, जो सांठगांठ नहीं है और जिसमें अचल संपत्ति का

कोई अधिकार प्रत्यक्ष रूप से और विशिष्ट रूप से विचाराधीन है, संपत्ति को किसी भी पक्ष द्वारा मुकदमे या कार्यवाही में स्थानांतरित या अन्यथा नहीं किया जा सकता है ताकि अदालत के अधिकार के तहत और ऐसी शर्तों के अलावा, जो वह लागू करे, उस डिग्री या आदेश के तहत किसी अन्य पक्ष के अधिकारों को लागू किया जा सके।"

इसलिए, यह स्पष्ट होगा कि वाद में प्रतिवादियों को धारा 52 के संचालन द्वारा संपत्ति से निपटने के लिए प्रतिबंधित किया गया था और वे अदालत के आदेश या प्राधिकरण के अलावा अपीलार्थी के अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी भी तरीके से इसका हस्तांतरण या अन्यथा सौदा नहीं कर सकते थे। मान लीजिए, उन संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए अदालत का अधिकार या आदेश प्राप्त नहीं किया गया था। इसलिए, स्पष्ट रूप से अलगाव

धारा 52 के संचालन से लिस पेंडेंस के सिद्धांत से प्रभावित होगा। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थियों को मुकदमे के लिए आवश्यक या उचित पक्षकार नहीं माना जा सकता है।

(बल दिया गया)

95. बीबी जुबैदा खातून बनाम नबी हसन साहब मामले में यह अदालत

और (2004) 1 एस. सी. सी. 191 में एक अन्य रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या उच्च न्यायालय का आदेश, जिसने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें अपीलार्थी के नेतृत्व में दायर किए गए आवेदनों को पक्षकार के रूप में खारिज कर दिया गया था। अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने सरविंदर सिंह (ऊपर) और धुरंधर के फैसलों का उल्लेख किया

प्रसाद सिंह बनाम जय प्रकाश विश्वविद्यालय और अन्य (2001) 6 में रिपोर्ट किए गए

एस. सी. सी. 534, और कहा कि:

"10. ... ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि अदालत की अनुमति के बिना हस्तांतरणकर्ता को सभी मामलों में लंबित मुकदमों में शामिल होने और लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।..."

(जोर दिया गया) 96। हम डी. एन. तनेजा बनाम भजन लाल में (1988) 3 एस. सी. सी. 26 में रिपोर्ट किए गए निर्णय का उल्लेख करना और उस पर भरोसा करना भी उचित हो सकता है, जिसके तहत यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अवमानना कार्यवाही में केवल दो पक्ष हैं, यानी अदालत और अवमानक। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"12. ... अवमानना अदालत और कथित अवमाननाकर्ता के बीच का मामला है। कोई भी व्यक्ति जो अवमानना के लिए अदालत की मशीनरी का रुख करता है, केवल अदालत की अवमानना करने वाले कुछ तथ्यों को अदालत के ध्यान में लाता है। ऐसी जानकारी देने के बाद भी वह अदालत की सहायता कर सकता है, लेकिन यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अवमानना की कार्यवाही में केवल दो पक्ष होते हैं, अर्थात् अदालत और अवमाननाकर्ता। यह उन कारणों में से एक हो सकता है जिसके कारण याचिकाकर्ता को अवमानना के लिए अपील करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। धारा 19 (1) के तहत पीड़ित पक्ष केवल अवमानक हो सकता है जिसे अदालत की अवमानना के लिए दंडित किया गया हो।"

(बल दिया गया)

1123

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1124 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

97. इस प्रकार, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के लिए अवमानना कार्यवाही में खरीदारों को शामिल करना आवश्यक नहीं था। वास्तव में, हम मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह देखने की हद तक जा सकते हैं कि खरीदार चुपचाप कार्यवाही देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा था, लेकिन जब चीजें गलत हो गईं, तो वे अब पक्षकारों के रूप में शामिल नहीं किए जाने और उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई न किए जाने की शिकायत करते

हैं। हम यह विश्वास करने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि जब बिक्री लेनदेन किए जा रहे थे तब भी उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए वचन के बारे में पता नहीं था कि मुख्य मामले के अंतिम निपटारे तक संपत्तियों को नहीं बेचा जाएगा।

अपील की अवधारणा

98. हमें 1971 के अधिनियम की धारा 12 का उल्लेख करना चाहिए:

“12. अदालत की अवमानना के लिए सजा।—

(1) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, अदालत की अवमानना को साधारण कारावास से दंडित किया जा सकता है जो छह महीने तक बढ़ सकता है, या दो हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों के साथ: बशर्ते कि अभियुक्त को आरोपमुक्त किया जा सकता है या अदालत की संतुष्टि के लिए माफी मांगने पर दी गई सजा को माफ किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण.—क्षमा याचना को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि यह योग्य या सशर्त है यदि अभियुक्त इसे प्रामाणिक बनाता है।

(2) तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय अपने या अपने अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में किसी भी अवमानना के लिए उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उस से अधिक सजा नहीं लगाएगा।

(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति दीवानी अवमानना का दोषी पाया जाता है, अदालत, यदि यह मानती है कि कोई व्यक्ति न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा और कारावास की सजा आवश्यक है, तो उसे साधारण कारावास की सजा देने के बजाय, निर्देश देगा कि उसे छह महीने से अधिक की अवधि के लिए दीवानी जेल में रखा जाए, जो वह समझता है।

(4) जहां न्यायालय को दिए गए किसी वचन के संबंध में न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया व्यक्ति एक कंपनी है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो अवमानना किए जाने के समय कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था, उसे अवमानना का दोषी माना जाएगा और अदालत की अनुमति से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को दीवानी जेल में नजरबंद करके सजा लागू की जा सकती है:

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी ऐसे व्यक्ति को ऐसे दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित करता है कि अवमानना उसकी जानकारी के बिना की गई थी या उसने इसे करने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

(5) उप-धारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उसमें निर्दिष्ट न्यायालय की अवमानना किसी कंपनी द्वारा की गई है और यह साबित होता है कि अवमानना किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारियों की सहमति या मिलीभगत से की गई है, या उनकी ओर से किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारियों को भी अवमानना का दोषी माना जाएगा और अदालत की अनुमति से ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारियों को दीवानी जेल में नजरबंद करके सजा लागू की जा सकती है।

स्पष्टीकरण.—उप-धारा (4) और (5) के प्रयोजनों के लिए, (क) "कंपनी" से कोई भी निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें एक निकाय या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

((ख) "निदेशक" का अर्थ है, "निदेशक" के संबंध में एक भागीदार।"

99. अधिनियम 1971 की धारा 12 अवमानना की सजा का प्रावधान करती है। इस धारा के प्रावधान में कहा गया है कि अभियुक्त को आरोपमुक्त किया जा सकता है या अदालत की संतुष्टि के लिए माफी मांगने पर दी गई सजा को माफ किया जा सकता है। इसके स्पष्टीकरण में कहा गया है कि माफी को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि यह योग्य या सशर्त है, 1125

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिजीजड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1126 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

यदि अभियुक्त इसे सही बनाता है। इसलिए, प्रावधान की आवश्यकता यह है कि कथित अवमानकर्ता द्वारा की गई माफी जो या तो योग्य है या सशर्त है, उसे भी खारिज नहीं किया जाएगा यदि अदालत की राय में इसे वास्तविक माना जाता है। यह अदालत का विवेकाधिकार है कि उसे स्वीकार किया जाए या नहीं और उस विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है और आरोपी को आरोपमुक्त किया जा सकता है। न्याय के मार्ग में हस्तक्षेप को रोकने और कानून के अधिकार को बनाए रखने के लिए, निश्चित रूप से, संविधान के तहत विचार की गई ऐसी शक्ति इसके उपयोग की गारंटी देती है।

100. अब हम माफी की स्वीकृति के संबंध में प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस स्तर पर यह ध्यान देना उचित है कि उच्च न्यायालय के समक्ष पूरी कार्यवाही के दौरान, अपीलकर्ताओं का रुख यह था कि उन्होंने अदालत को एक स्पष्ट वचन देने के बावजूद बिक्री विलेखों को निष्पादित करके एक बड़ी गलती की कि वे ऐसा नहीं करेंगे। कुल मिलाकर, उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में निर्दिष्ट समय की अवधि के दौरान अपीलार्थियों के नेतृत्व में विभिन्न मामलों में किए गए बयानों से यह रुख रहा था कि अपीलार्थियों को उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी और इस संबंध में उन्हें अत्यंत खेद है। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अनुरोध किया कि उनकी माफी स्वीकार की जा सकती है और उन्हें कार्यवाही से मुक्त किया जा सकता है।

101. हम अपने आदेश पर पूरी विनम्रता के साथ इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि समय के साथ, अदालतों ने अवमानकों के प्रति अनुचित नरमी और उदारता दिखाई है। कुछ समय से अदालतों द्वारा दिखाए गए इस उदार रवैये ने वास्तव में बेईमान वादियों को किसी भी अदालत द्वारा पारित आदेश या अदालत को दिए गए किसी भी वचन का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

102. अदालत की अवमानना के लिए आगे बढ़े वादियों ने महसूस किया है कि उनके हाथों में माफी के रूप में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। उदाहरण के लिए, वर्तमान मामले को ही लें। अपीलार्थी क्या चाहते हैं कि हम क्या करें? अपीलार्थी चाहते हैं कि यह न्यायालय उनकी माफी स्वीकार करे और उच्च न्यायालय द्वारा पारित सजा और सजा के आदेश को रद्द कर दे। अदालतों द्वारा करुणा दिखाने की प्रवृत्ति तब नहीं होनी चाहिए जब किसी वचन या आदेश की अवज्ञा दंड से मुक्त और पूरी चेतना के साथ हो।

103. री में। तपन कुमार मुखर्जी बनाम हीरोमोनी मंडल और

(1991) 1 एस. सी. सी. 397 में एक अन्य रिपोर्ट, इस न्यायालय ने एक अवमानना मामले में टिप्पणी की है:—

“9.... हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि जहां जानबूझकर अवज्ञा का मामला बनाया जाता है, वहां अदालतें संकोच नहीं करेंगी और दोषी अधिकारियों को दोषी ठहराएंगी और अदालत से अदालत के रवैये में कोई नरमी की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए क्योंकि निश्चित रूप से केवल इस आधार पर कि दोषसिद्धि का आदेश संबंधित अधिकारी के सेवा करियर को नुकसान पहुंचाएगा।

104. री में। तपन कुमार (ऊपर), यह न्यायालय अवमानना के लिए कार्रवाई का सामना कर रहे एक लोक सेवक से निपट रहा था।

105. हम आश्चर्य करते हैं कि अंतिम परिणाम क्या हो सकता है यदि हम माफी स्वीकार करते हैं और अपीलकर्ताओं को मुक्त होने देते हैं। पहला, उन्हें अवमानना के कथित कार्य के लिए किसी कानूनी परिणाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और दूसरा, वे अपनी अवमानना का लाभ उठाते रहेंगे या अपने पास रखते रहेंगे। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे पहले से ही खरीदारों से प्राप्त बिक्री प्रतिफल के लिए एक बड़ी राशि जमा कर चुके हैं।

106. उप-न्यायाधीश के मामले में, प्रथम श्रेणी, होशंगाबाद बनाम जवाहर

लाल रामचंद परवर ने ए. आई. आर. 1940 नागपुर 407 में रिपोर्ट किया, न्यायमूर्ति बोस (जैसा कि वे तब थे) ने कहा कि माफीनामा बचाव का हथियार नहीं है जो दोषियों को उनके अपराधों से मुक्त करने के लिए बनाया गया है। जिन लोगों पर अन्याय किया गया है, उनके सिर पर फेंका जाना कोई अतिरिक्त अपमान नहीं है। इसका उद्देश्य वास्तविक पश्चाताप, गलत किए जाने की पुरुष भावना, चोट लगने की भावना और गलत करने वाले की शक्ति में निहित ऐसी क्षतिपूर्ति करने की गंभीर इच्छा का प्रमाण

होना है। एक क्षमा याचना, जिसे विद्वान न्यायाधीश कहते हैं कि गलत किए जाने के बारे में वास्तविक पश्चाताप और मर्दाना चेतना का प्रमाण होना चाहिए; अगर देर हो जाती है तो ऐसा होना बंद हो जाता है, और इसके बजाय, न्यायमूर्ति बोस की भाषा को उधार लेना, फिर से न्याय के कठोर हाथ के उसके सिर पर उतरने की संभावना पर कांपते हुए एक कायर की कराह बन जाता है।

107. पटेल रजनीकांत धुलाभाई (ऊपर) के मामले में, यह न्यायालय

इस तर्क को खारिज कर दिया कि माफी का उपयोग बचाव के हथियार के रूप में किया जा सकता है और नीचे दिए गए कई निर्णयों पर भरोसा किया जा सकता है:

1127

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1128 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

"62. महान्यायवादी बनाम टाइम्स न्यूजपेपर लिमिटेड [(1974) ए. सी. 273 के प्रसिद्ध निर्णय में: (1973) 3 सभी ईआर 54: (1973) 3 डब्ल्यूएलआर 298 (एचएल)] लॉर्ड डिप्लॉक ने कहा: (सभी ई. आर. पी. 71 एफ)

"नागरिक अवमानना को दंडित करने में सार्वजनिक नीति का एक तत्व है, क्योंकि यदि किसी भी अदालत के आदेश की दंड से मुक्ति के साथ अवहेलना की जा सकती है तो न्याय के प्रशासन को कमजोर किया जाएगा।" × × ×

× × ×

× × ×

74. हीरेन बोस में, रे [ए. आई. आर. 1969 कैल 1:72 कैल डब्ल्यू. एन. 82] कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा: (ए. आई. आर. पी. 3, पैरा 13)

"13. ... यह भी निश्चित रूप से कोई बात नहीं है कि एक न्यायाधीश से किसी भी माफी को स्वीकार करने की उम्मीद की जा सकती है। क्षमा याचना बचाव का एक हथियार नहीं हो सकता है जो हमेशा दोषियों को शुद्ध करने के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य वास्तविक पश्चाताप, गलत किए जाने की पुरुष चेतना, चोट लगने की भावना और गलत करने वाले की शक्ति में निहित ऐसी क्षतिपूर्ति करने की गंभीर इच्छा का प्रमाण होना है। तभी न्याय की अदालत में इसका कोई लाभ होगा। लेकिन इससे पहले कि यह प्रभावी हो सके, इसे जल्द से जल्द संभव चरण में निविदा दी जानी चाहिए, न कि नवीनतम। भले ही ज्ञान केवल बाद के चरण में ही प्रकट होता है, न्यायाधीश द्वारा अपने मन की प्रवृत्ति का संकेत देने से पहले माफी को बिना किसी शर्त के प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक न केवल मांगी गई माफी से सारी कृपा छीन ली जाती है, बल्कि यह माफी नहीं रह जाती है। यह एक गलत किए जाने का पूर्ण, स्पष्ट और मर्दाना स्वीकारोक्ति होना बंद हो जाता है, जो इसका इरादा है।"

75. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि माफी न तो दोषियों को उनके अपराध से मुक्त करने के लिए बचाव का एक हथियार है, न ही इसका उद्देश्य एक सार्वभौमिक रामबाण के रूप में काम करना है, इसका उद्देश्य वास्तविक पश्चाताप का प्रमाण होना है (एम. वाई. शरीफ बनाम नागपुर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों [ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 19: (1955) 1 एससीआर 757]; एम. बी. संघी बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय [(1991) 3 एस. सी. सी. 600: 1991 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 897: (1991) 3 एससीआर 312])।

76. टी. एन. गोडावर्मन थिरुमुलपद (102) बनाम अशोक खोट (2006) 5 एस. सी. सी. 1) मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अवमानकर्ता द्वारा बचाव के एक हथियार के रूप में "माफी" के आलोक में इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर दिया था। अदालत ने लिया

एल. डी. जयक्वाल बनाम यू. पी. राज्य [(1984) 3 एस. सी. सी. 405 में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दें: 1984 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 421]: (अशोक खोट मामला [(2006) 5 एससीसी 1], एससीसी पी। 17, पैरा 32)

"32. ... हमें यह कहते हुए खेद है कि हम अवमानना न्यायशास्त्र के प्रशासन में 'थप्पड़-क्षमा करें-और भूल जाओ' विचारधारा की सदस्यता नहीं ले सकते हैं।'क्षमा करें' कहने का मतलब यह नहीं है कि कथित पाखंडी शब्द के उच्चारण पर थप्पड़ मारने वाला कम होशियार हो जाता है।माफी कागजी माफी नहीं होनी चाहिए और दुख की अभिव्यक्ति दिल से आनी चाहिए न कि कलम से।क्योंकि 'सॉरी' कहना एक बात है-'सॉरी' कहना दूसरी बात है।"

इसलिए, न्यायालय ने प्रार्थना को खारिज कर दिया और कहा:(एस. सी. सी. पी. 17, पैरा 31)

"31. क्षमा याचना पश्चाताप का कार्य है।जब तक माफी को जल्द से जल्द अवसर पर और अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक माफी को पश्चाताप से अलग किया जाता है और इसलिए इसे अस्वीकार किया जा सकता है।यदि माफी उस समय स्वीकार नहीं की जाती है जब अवमानकर्ता यह मानता है कि अदालत सजा देने जा रही है तो यह माफी देना बंद कर देता है और एक डरपोक कायरता का कार्य बन जाता है।"

इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा अन्य मामलों में भी लिया गया था।

77. हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि तथाकथित माफी पश्चाताप, पश्चाताप या अफसोस का कार्य नहीं है।इसे एक "चतुराईपूर्ण कदम" के रूप में प्रस्तुत किया गया है जब अवमानकर्ता तंग कोने में होते हैं और अदालत को दूर करने के उद्देश्य से होते हैं।हाथ में मामले में इस तरह की माफी की स्वीकृति अवमानकर्ताओं को अदालत की घोर अवमानना करने के बाद दंड से मुक्त होने की अनुमति देगी।हमारी सुविचारित राय में, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, कारावास के बदले में एफ. आई. एन. ई. का अधिरोपण न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा।"

(बल दिया गया)

108. इस न्यायालय ने प्रिया गुप्ता और एक अन्य बनाम अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य मामले में (2013) 11 में रिपोर्ट दी।

एस. सी. सी. 404 ने कहा कि:

"7. माफी मांगना अवमानना कार्यवाही को हल करने का संतोषजनक तरीका नहीं है।1129 के शुरुआती चरण में मांगी गई माफी

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1130 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

कार्यवाहियों के प्रामाणिक होने और अधिमानतः बिना शर्त होने से आम तौर पर अदालत को इस तरह की माफी स्वीकार करने के लिए राजी किया जाएगा, अगर यह अदालत की गरिमा/अधिकार पर गंभीर धब्बा नहीं छोड़ेगा और अदालत के आदेशों के तहत न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा।8. "बोना फाई डी "एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसकी जांच किसी दिए गए मामले के संदर्भ में की जानी चाहिए।इसे अमूर्त में नहीं समझा जा सकता है।परिचर परिस्थितियां, अवमानकर्ता का व्यवहार और उसकी ओर से पश्चाताप या पश्चाताप कुछ प्रासंगिक विचार हैं जो इस तरह के मुद्दे पर निर्णय लेने में न्यायालय के साथ विचार करेंगे। जहां, लगातार, किसी व्यक्ति ने न्यायालय की प्रक्रिया को दरकिनार करने का प्रयास किया है और न्यायालय के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए किए गए अवैध कार्य को जारी रखा है, तो न्यायालय के लिए बिना शर्त माफी स्वीकार करना मुश्किल होगा, भले ही वह कार्यवाही की सीमा पर की गई हो।हमारे लिए मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स की अधिक विस्तार से जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अदालत के आदेशों के तहत निर्धारित अनुसूची की अवज्ञा, प्रक्रिया में हेरफेर और उल्लंघन एक स्वीकृत स्थिति है।हमें केवल इस बात की जांच करनी है कि क्या प्रस्तुत की गई माफी परिचर परिस्थितियों के आलोक में जांच किए जाने पर वास्तविक है और क्या इसे स्वीकार करना न्याय के हित में होगा।

9. क्षमायाचना की स्वीकृति पर विचार करते समय न्यायालय के साथ जिन तथ्यों पर विचार किया जाएगा, वे हैं अवमाननापूर्ण आचरण, जिस हद तक न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया है, अवमाननाकर्ता की ओर से गैर-जिम्मेदाराना कार्य और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप की डिग्री, जिससे अन्य पक्षों के लिए पूर्वाग्रह पैदा होता है।शुरू में भी मांगी गई माफी वास्तविक होनी चाहिए और अवमानकर्ता की ओर से पश्चाताप और ईमानदारी से खेद का प्रदर्शन होना चाहिए, ऐसा न हो कि न्याय के प्रशासन में दंड से मुक्त व्यक्ति द्वारा क्रूरता से हस्तक्षेप किया जाए।कानून के शासन के मूल अवयवों को लागू करना होगा, चाहे

कोई भी परिणाम हो और सभी व्यक्ति कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक मौलिक कर्तव्य के अधीन हैं। एक माफी जो वास्तविक नहीं है और अदालत के आदेशों के इस तरह के घोर उल्लंघन के परिणामों से बचने के गुप्त उद्देश्य से कानून की प्रक्रिया को कम करने के लिए दी गई है और प्रशासन के पाठ्यक्रम के प्रति स्पष्ट अनादर का कारण बनती है।

न्याय की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत को उन मामलों के बीच संतुलन बनाना होता है जहां माफी मांगना पर्याप्त है, और उन मामलों के बीच जहां अवमानना करने वाले को सजा देना आवश्यक है। न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करने का प्रयास न्यायालय और न्याय प्रशासन की गरिमा के लिए अपमानजनक है। एक व्यक्ति जो अदालत के आदेश के बारे में अज्ञानता दिखाकर खुद को बचाने का प्रयास करता है, जिसके बारे में उसे स्पष्ट रूप से जानकारी थी, वह फिर से कानून की प्रक्रिया को दरकिनार करने का प्रयास होगा। एक औचित्य प्रदान करना माफी की अवधारणा के साथ असंगत होगा। एक माफी जो न तो ईमानदार है और न ही संतोषजनक है और उचित स्तर पर नहीं की गई है, उसे स्वीकार करने के लिए अदालत को पर्याप्त आधार प्रदान नहीं कर सकती है। यह भी एक स्वीकृत सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जानबूझकर उल्लंघन करता है, उसे भी इसके परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। जो व्यक्ति अयोग्य माफी मांगता है, वह आम तौर पर अवमाननापूर्ण आचरण के लिए न्यायसंगत नहीं होगा। किसी भी मामले में, माफी मांगना अवमानकर्ता द्वारा अपराध के अपराध को दूर करने के लिए बचाव का एक हथियार है। इसका उद्देश्य कानून में कार्रवाई को विफल करने के लिए एक सार्वभौमिक रामबाण के रूप में काम करना नहीं है, क्योंकि मूल सिद्धांत यह है कि कानून का शासन और अदालत की गरिमा प्रबल होनी चाहिए।

×××

×××

×××

14. उपरोक्त सिद्धांत से, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 12 (1) के स्पष्टीकरण के तहत क्षमा याचना पर विचार करना सार्वभौमिक रूप से कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए रामबाण नहीं है। क्षमा याचना और उसकी स्वीकृति पर विचार करते समय, अदालत अन्य बातों के साथ-साथ विचार करती है: (क) क्षमा याचना करने से पहले और बाद में अवमानकर्ता का आचरण। यदि आचरण अवमाननापूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण है और इसने व्यवस्था और समग्र रूप से अन्य निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया है, तो यह एक ऐसा कारक होगा जो अवमानकर्ताओं के खिलाफ होगा; और (बी) वह चरण और समय जब ऐसी माफी दी जाती है।

(बल दिया गया)

109. सेवक (ऊपर) के मामले में, यह माना गया था कि एक माफी न तो अवमानना के कार्य को शुद्ध करती है और न ही धोती है और सबसे अच्छा यह 1131 है।

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1132 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

अवमानना की समाप्ति के बाद परिणामी आदेश पर विचार करते हुए परिस्थितियों को कम करना। प्रासंगिक भाग यहाँ प्रस्तुत किया गया है:

"46. दोनों पक्षों द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न निर्णयों को हमें लंबे समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तय किए गए मामलों में सिद्धांत रूप में कोई भेद नहीं है। क्षमा याचना बचाव का हथियार नहीं है। क्षमा याचना न तो अवमानना के कार्य को शुद्ध करती है और न ही दूर करती है। एक बार जब किसी व्यक्ति को दीवानी या आपराधिक अदालत की अवमानना करते हुए पाया जाता है, तो किए जाने वाले परिणामी आदेशों पर विचार करते समय यह सबसे कम करने वाली परिस्थिति होती है। अवमानकर्ता के खिलाफ किए जाने वाले आदेश को तैयार करते समय यह एक प्रासंगिक कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। क्षमा याचना पर केवल वही विचार किया जा सकता है जो वास्तविक अर्थों में पश्चातापपूर्ण हो और न्यायालय की संतुष्टि के लिए उत्तरदाताओं द्वारा पश्चाताप के रूप में हो। आम तौर पर, विलंबित माफी को पश्चाताप की भावना की तुलना में सजा के डर से अधिक माना जाता है। लेकिन केवल इसलिए कि माफी की पेशकश की गई है, पहली बार में नहीं, बल्कि बाद के चरण में, अपने आप में इस पर विचार नहीं करने का आधार नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता, तो सेक को परंतुक। 12 जिससे सजा दिए जाने

के बाद भी, उसके बाद दी गई माफी पर विचार करने पर उसे माफ करना संभव हो जाता है। संक्षेप में, कार्यवाही के किसी भी चरण में दी गई माफी को कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में माना जाना चाहिए या नहीं, यह उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और यह सिद्धांत किसी भी मिसाल से बाधित नहीं होता है। मिसालें दिशानिर्देशों के रूप में काम करती हैं "।

(जोर दिया गया) 110। एम. वाई. शरीफ और एक अन्य मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ

v. नागपुर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों और अन्य ने आकाशवाणी में रिपोर्ट किया

1955 एस. सी. 19 ने इस प्रकार कहा:

"10. प्रस्ताव अच्छी तरह से तय किया गया है और स्वयं स्पष्ट है कि औचित्य और माफी दोनों नहीं हो सकते हैं। ये दोनों बातें बेमेल हैं। क्षमा याचना दोषियों को उनके अपराध से मुक्त करने के लिए बचाव का हथियार नहीं है और न ही इसका उद्देश्य एक सार्वभौमिक रामबाण के रूप में काम करना है, लेकिन इसका उद्देश्य वास्तविक पश्चाताप का प्रमाण होना है। अपीलकर्ताओं ने एक अयोग्य माफी याचिका दायर की है, उच्च न्यायालय के फैसले में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है कि स्थानांतरण के लिए आवेदन

यह अवमानना का गठन करता था क्योंकि न्यायाधीशों को न्याय के उचित मार्ग को मोड़ने की दृष्टि से बदनाम किया गया था, और इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने में दोनों अधिवक्ता अवमानना के दोषी थे। इसलिए यह निर्णय कायम है।"

(जोर दिया गया) 111। इस प्रकार, माफी केवल एक शब्द नहीं है। अदालत को माफी स्वीकार नहीं करनी चाहिए जब यह प्रतीत होता है कि माफी मांगना जिम्मेदारी से बाहर निकलने के लिए एक कानूनी चाल के अलावा और कुछ नहीं है। एक सच्ची माफी आत्मनिरीक्षण, आत्म-आत्मनिरीक्षण, प्रायश्चित और आत्म-सुधार का एक गहरा नैतिक कार्य होना चाहिए। इसकी अनुपस्थिति में, माफी को प्रहसन कहा जा सकता है।

112. यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि दी गई माफी को निश्चित रूप से एक मामले के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और अदालत इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि, माफी बिना शर्त, अयोग्य और प्रामाणिक हो सकती है, फिर भी, यदि आचरण गंभीर है जिससे संस्था की गरिमा को नुकसान पहुंचा है, तो इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

113. मामले के तथ्यों में, हम आश्चर्य हैं कि हालांकि अपीलकर्ताओं ने पहली बार में उच्च न्यायालय के समक्ष माफी मांगी होगी, फिर भी ऐसी माफी स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं की गई थी। यह और कुछ नहीं बल्कि अपीलार्थियों की ओर से एक जुआ था। यह कहना उनकी ओर से एक लंगड़ा बहाना है कि उनके पास बिक्री विलेखों को निष्पादित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने इस संबंध में कुछ परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला है। हालाँकि, हम अपीलार्थियों द्वारा दिए गए ऐसे किसी भी स्पष्टीकरण से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। उन्होंने संपत्तियों को हस्तांतरित करने के लिए एक सोचा-समझा जोखिम उठाया और बिक्री पर विचार किया। यदि बिक्री विलेखों को निष्पादित करने की कोई आसन्न तात्कालिकता थी, तो वे उच्च न्यायालय में आ सकते थे और उन्हें इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण या अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी। यही कारण है कि हम कहते हैं कि अपीलकर्ताओं ने गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने के लिए इस उम्मीद में जुआ खेला कि अंततः वे माफी मांगकर भाग जाएंगे। यही कारण है कि अदालत द्वारा इस तरह की नकली माफी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और एक ऐसे व्यक्ति को कानूनी परिणामों से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसे कानून की महिमा के लिए कोई सम्मान नहीं है। हमारे लिए कोई करुणा दिखाने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि अवमानना की गई है और उचित संदेह से परे साबित हुई है और इस अवमानना का प्रभाव महामहिम उच्च न्यायालय पर महसूस किया गया है। मुकदमेबाजी करने वाली जनता को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति जारी रह सकती है या अदालत 1133 तक नहीं बढ़ेगी।

बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल

सोमाभाई कॉन्ट्रैक्टर (डिसीज्ड) रिप। एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1134

इसके आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का अवसर। कानून बहुत स्पष्ट है कि अदालत को सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए और अभियोग को कमजोर नहीं करना चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ इसका पालन नहीं करना

चाहिए। यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं ने अवमानना की है, संदेह में नहीं है। कानून यह आदेश देता है कि सजा का पालन किया जाना चाहिए।

114. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा का मुद्दा भी उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने इसका काफी विस्तार से जवाब दिया है। वास्तव में, इन अपीलों की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा हमारे सामने नहीं उठाया गया था। हमें सीमा के मुद्दे में आगे जाने की आवश्यकता नहीं है।

115. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया है। हमने उन सभी फैसलों पर गौर किया है। अपीलार्थियों के लिए किसी भी निर्णय का कोई लाभ नहीं है। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम अपीलार्थियों की ओर से दिए गए प्रत्येक निर्णय पर विचार करें। हमने अदालत की अवमानना से संबंधित सभी मुद्दों पर कानून की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की है।

116. हम अपने अंतिम निष्कर्ष को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं:

(i) हम मानते हैं कि अदालत को अपने मुवक्किल की ओर से एक वकील/अधिवक्ता द्वारा दिए गए वचन के रूप में एक आश्वासन; उसका जानबूझकर उल्लंघन या अवज्ञा अधिनियम 1971 की धारा 2 (बी) के तहत "नागरिक अवमानना" के बराबर होगी।

((ii) किसी पक्ष को दिए गए वचन और अदालत को दिए गए वचन के बीच अंतर होता है। अदालत को दिया गया वचन अधिनियम 1971 के प्रावधानों को आकर्षित करता है, जबकि समझौते के समझौते के माध्यम से या अन्यथा किसी पक्ष को दिया गया वचन अधिनियम 1971 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम मानते हैं कि वचन उच्च न्यायालय को दिया गया था और उल्लंघन या अवज्ञा अधिनियम 1971 के प्रावधानों को पूरी तरह से आकर्षित करेगी।

((iii) यद्यपि मुकदमे की संपत्ति के हस्तांतरण को शुरू से ही अमान्य नहीं कहा जा सकता है, फिर भी जब अदालत अवमानना की कार्यवाही में ऐसे हस्तांतरणों पर विचार कर रही है तो अदालत कानून की महिमा बनाए रखने के लिए ऐसे लेनदेन को अमान्य घोषित कर सकती है। अपमान करने वाले को दंडित करने के अलावा, उसके दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

आचरण, कानून की महिमा की मांग की जा सकती है कि अदालत द्वारा उचित निर्देश जारी किए जाएं ताकि इस तरह के आपत्तिजनक आचरण के परिणामस्वरूप प्राप्त कोई भी लाभ पूरी तरह से अमान्य हो जाए। इसमें या तो ऐसे लेन-देन को अमान्य घोषित करके लेन-देन को वापस करने के लिए निर्देश जारी करना या संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देना शामिल हो सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवमानकर्ता की ओर से अनुचित आचरण अवमानकर्ता या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के लाभ के लिए जारी न रहे।

((iv) किसी भी आपत्तिजनक लेन-देन के हितग्राहियों को अवमानना की कार्यवाही में इस आधार पर सुनवाई का कोई अधिकार या अधिकार नहीं है कि वे बिना किसी सूचना के संपत्ति के वास्तविक खरीदार हैं और इसलिए वे आवश्यक पक्ष हैं। अवमानना अदालत और अवमानकर्ता के बीच होती है और कोई तीसरा पक्ष इसमें खुद को शामिल नहीं कर सकता है।

(v) दी गई माफी को निश्चित रूप से एक मामले के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और अदालत इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। माफी बिना शर्त, अयोग्य और वास्तविक हो सकती है, फिर भी यदि आचरण गंभीर है, जिसने संस्थान की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अदालतों में करुणा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, जब किसी वचन या आदेश की अवज्ञा दंड से मुक्त और पूरी चेतना के साथ हो।

117. परिणामस्वरूप, तीनों अपील विफल हो जाती हैं और इसके द्वारा खारिज कर दी जाती हैं। 118. हम अपीलार्थियों को आत्मसमर्पण करने और उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा पूरी करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हैं।

119. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

